[श्री राम विलास पासवान]

सब लोगों को बुला कर कोई रास्ता निकालिये (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If the matter was not serious enough, the Statement would not have been made by the Government. The very fact that they have made the statement shows that they are seriously concerned about it.

SHRI SURAJ BHAN: But that is not enough.

MR. CHAIRMAN: You can give a notice to this effect so that the Government can consider it.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : इस मामले में हम सभी सरकार क साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हम सब आपके साथ हैं। पंजाब के मामले में आपको सदन को डार्क में नहीं रखना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: Give it in writing.

15.06 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANTS (GENERAL) 1982-83—contd

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जनाब, मैं यह कह रहा था कि जब आप अपने वायदे में फल हो गये तो आपने आई० एम० एफ० लोन लने की कोशिश की। मैं यह मानता हूं कि कुछ खास वजूहात में आई० एम० एफ० से लोन लना या उसके लिए कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सरकार को यह भी बहुत संजीदगी से सोचना चाहिये था कि आई० एम० एफ० से लोन लने के बाद भी अगर हम इस दलदल से नहीं निकल सक तो क्या होगा। इसलिए आई० एम० एफ० से लोन लेने से बेहतर यह था कि हम अपनी प्लानिंग को, अपनी वर्जटिंग को, अपनी मशीनरी को दुरस्त करते। अगर आई० एम० एफ० से लोन लेने के बाद भी हम इस दलदल से नहीं निकलते हैं तो हमारे पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। तमाम रास्ते हमारे बंद हो जायेंगे। इसलिए हमें अपनी प्लानिंग को, अपनी बजटिंग को, अपनी मशीनरी को दुरुस्त करना चाहिये। अब तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा और आई० एम० एफ० से लोन लेना बेहतर समझा।

जहां तक हमारे फोरन एक्सचेंज और फोरन रिजर्व का सवाल है, वह भी गिरता जा रहा है। जब हम 1977 में सरकार में आये थे तो उस वक्त 26 सौ करोड़ रुपये के करीब हमारा फोरन रिजर्व था। लेकिन जब हमने 1979 में सरकार को छोड़ा तो उस वक्त हमारे मुल्क के पास 53 सौ करोड़ रुपये फोरन रिजर्व था। यह दूसरी बात है कि आपने बाहर यह कह दिया कि हमने फोरन एक्सचेंज को फोरन रिजर्व को खत्म कर दिया, हमने मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया। यह आपका ही रिकार्ड है और उस रिकार्ड के मुताबिक हमने 53 सौ करोड़ रुपये का रिजर्व छोड़ा था। आज आपकी क्या हालत है ? आपके पास आज 35 सौ करोड़ रुपये का फोरन रिजर्व है इसमें भी 15 सौ करोड़ रुपये जो आपको आई० एम० एफ० की किस्त मिली है, उसका है। अगर 35 सौ करोड़ फुपये में से इस 15 सौ करोड़ रुपये को घटा दिया जाए तो सिर्फ 19 सौ करोड़ रुपये का फोरन रिजर्व बचता है। यह है आज की हालत, यह है आज का फेक्ट जिसके लिए

आप दिन-रात कहते हैं कि हम सेल्फ रिलाइंस की तरफ जा रहे हैं। क्या यह सेल्फ रिलाएंस है ?

इसके लिए आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। बजाए सेल्फ रिलाइंस की तरफ बढ़ने के आपने मल्टी नेशनल्स को इन्वाइट किया, आई० एम० एफ० और दूसरे इरादों से लोन लिया। हमने कई दफा आपको सजेशन दिया कि दुनिया के मुल्कों में जो हमारे हिन्दुस्तानी रहते हैं उनसे हम दरख्वास्त करें कि वे अपने मुलक में इन्वेस्टमेंट करें। एकोनोमिक टाइम्स के सर्वे के मुताबिक करीब 90 हजार करोड़ रुपया हमारे हिन्दुस्तानी भाई दूसरे मुमालिक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारी सरकार इस ओर काफी सीरियस होती तो वह इस मसले पर गौर करती और आई० एम० एफ० से लोन लेने के बजाए अपने हिन्दुस्तानी भाइयों से जो यहां से चले गए हैं और दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनसे दरख्वास्त करती कि वे अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि दस-बीस परसेंट इन्वेस्टमेंट कराने में सरकार कामयाब हो जाती।

एक बहुत बड़ी प्राब्लम साल्व हो जाती।

PROF. N. G. RANGA (Guntur): It cannot be more than hundred. crores. You need thousands of crores.

SHRI RASHEED MASOOD: It will be more than 5000 crores, which you have obtained from the IMF.

हमारी एंबेसीज की क्या हालत है विदेश में रहने वालों की कभी गैदरिंग नहीं होती, कभी उनको बुलाया नहीं जाता। कई बार तो उनके पास उनके नाम-पते भी नहीं होते। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। हमें तो यह देखना है कि आज देश की क्या हालत है।

आज बंगाल में देखिए खुश्कसाली भी है, कहते भी है। वहां पर पब्लिक बहुत परेशानी में है। उड़ीसा की हालत देखिए। वहां हालात इतने खराब है कि ट्रक्स में जो माल जाता है, उसको छीन लिया जाता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है आफिसर्स जो सामान लेकर जाते हैं वह भी उनसे छीन लिया जाता है। अभी बिहार में संथाल परगने का वाक्या आपके सामने है। आप भले ही कुछ भी कहते रहें कि कोई बात नहीं है, लेकिन आज देश की हालत बहुत खराब है। आज ही हिन्दुस्तान टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में बिहार, उड़ीसा की हालत के बारे में आया है वहां भुखमरी है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में खुश्कसाली है। बाकी जिलों में पानी आ गया है। जहां खुश्कसाली है वहां 45 से 65 फीसदी तक फसलें तबाह हो गई हैं और जहां सैलाब आ गया है वहां 50 फीसदी और कहीं-कहीं तो मुकम्मल तौर पर फसलें तबाह हो गई है। बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा की यह हालत है। राजस्थान के बारे में भी अभी इन्होंने बताया। इस तरह से 5–6 राज्यों की हालत बहुत खराब है। हरियाणा में हालांकि खुश्कसाली का असर नहीं होता है, लेकिन इस मरतबा हुआ है इसकी वजह है कि आपने एशियाड कराने का फैसला किया। उस पर आपने 12 सौ करोड़ रुपया खर्च किया, जिस देश में लोगों के पास दो वक्त की रोटी न हो, वहां तमाशे पर इतना रुपया खर्च हो रहा है। खैर उसको छोड़िए लेकिन वह बिजली जो हरियाणा ; टयूबवेल्स को मिलनी चाहिए वह उस किसान को न मिलकर जो आपको खाने के लिए गेहू देता है, एशियाड गेमश्स के लिए दी जाती है। कभी ऐसा नहीं

[श्री रशीद मसूद]

हुआ । हरियाणा की तारीख में अभी तक ट्यूबवेल्स के लिए इस तरह से बिजली नहीं काटी गई । इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है । यू पी में भी जहां खुश्कसाली है, वहां भी किसानों को 6 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है । 1977 से 79 तक जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी खुश्कसाली का वक्त आया था, लेकिन हमने सबसे पहले यह फैसला लिया कि बड़े-बड़े शहरों को बिजली कम दे कर वह बिजली देहातों में किसानों को ट्यूबवेल्स के लिए दी थी । इस तरफ ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आज जो 25 लाख टन गेहूं का आयात किया है यह कहीं 5000 टन न हो जाए । आप कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि हालात ठीक नहीं है। असाम और पंजाब की बात तो रोजमर्रा की हो चुकी है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है कि रूरल री कंट्रैक्शन डिपार्टमेंट मालम नहीं कहां वर्क कर रहा है ?

रूरल रि-कंस्ट्रक्शन की बजाय रूरल डवलपमेन्ट हो गया है, तो बहुत ही अच्छा नाम है। लेकिन रूरल डवलपमेन्ट आपका कहां है, वह तो डवलपमेन्ट नहीं कर रहा है। हमें याद है, आप किसी भी देहात में चले जाइए । सन् 1977 से 1980 के दर्म्यान कुछ सड़कें बनी हैं फूड फार वर्क के डि-पार्टमेन्ट के नाम से । लिहाजा जरूरत आपको इस बात की पेश आई कि इसका फायदा जनता वाले न उठाएं और इसलिए इसका नाम बदल दिया जाए । नाम बदल देते और काम वहीं रहता तो हमें शिकायत न होती और हम आपको सपोर्ट करते । लेकिन आपने नाम बदलने के साथ-साथ काम भी बदल दिया क्योंकि आपकी नीयत देहात में कुछ काम करने की नहीं है । लिहाजा आप किसी भी देहात में चले जाइए । आपकी गवर्मेन्ट को ढाई तीन साल हो गए है । जहां एक कि० मी० की सड़क भी बनी हुई है, वहां चले जाइए । जितने मजदूर सड़क बनाने में लगाए जाते थे, उनको ही अनाज दिया जाता था लेकिन आपने सब बन्द कर दिया है ।

जैसा मैंने बताया आज सूखे की हालत है, उसमें हर आदमी को बहुत सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं । आपके बजट में ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप कोई प्राविजन रख रहे हैं कि आपका कुछ कन्सर्न है या आप परेशान हैं । आपकी प्लानिंग में कोई खास चेंज दिखाई नहीं देता । मैं चाहूंगा कि हमारे मिन्स्टिर साहब बताएं कि वे इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं । कहना तो बहुत चाहता था लेकिन आप घंटी बजा देते हैं और जो दिमाग में ख्यालात होते हैं वह भी मुन्तशिर हो जाते हैं । सिर्फ एक बात कहकर खत्म कर दूंगा, एजकेशन के सिलसिले में ।

यहां पर कुछ साहेबान ने खड़े होकर एतराज किया, बंगाल की सरकार का। बंगाल की सरकार मेरी नहीं है, लिहाजा यह न समझिए कि उस सरकार के लिए, लेकिन अगर एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हम समझते हैं कि हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए । अगर वह वेसे का वैसा ही पड़ा हुआ है और कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं तो कम्पलीट फेल्योर हो रहा है । आज तमाम यूनिवर्सिटीज में हंगामा है, क्योंकि अपने

सिस्टम ने यूथ में फस्ट्रेशन पैदा कर दिया है ।

पहले प्लानिंग में आपने 7 फीसदी अपने बजट का रखा था एजुकेशन पर और आज 2 फीसदी खर्ज कर रहे हैं जबकि उसके मुकाबले में अब ज्यादा जरूरत हो गई है । किस तरफ आप मुल्क को ले जाना चाहते हैं ।

आप कन्सेशन देना चाहते हैं । जब भी आपका बजट में रिलीफ आया तो कन्सेशन किसको मिला-इन्डस्ट्रीयलस्टि को, इस मर्तबा किसको मिला-इन्डस्ट्रीयलिस्ट को आइंदा किसको मिलेगा इन्डस्ट्रीयलिस्ट को । इस मुल्क के गरीब के लिए तालीम जरूरी है, लेकिन आप एजुकेशन बजट को दिन-ब-दिन घटाते जा रहे हैं । मैं सिर्फ बजट की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि आपको सस्टिम के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आप उसमें तब्दीलियां ला सकते हैं ।

हम पार्लियामेंटरी फोरम आफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च आरगेनाइजेशन की तरफ से एक कन्वेशन फरवरी में करने जा रहे हैं । उसमें आप सभी लोगों को दावत है, उसमें मदद करें और देखें। वहां हम यह चाहते हैं कि कोई फार्मूला निकाला जाए कि एजुकेशन सिस्टम में क्या खराबी है और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए । यह चंद चीजें आपको बतायीं । चूंकि टाईम कम है इसलिए आप इन चीजों पर गौर करें कि आपका प्लानिंग तो डिफेक्टिव नहीं है और आपका सिटस्म जो इसको इम्लीमेंट करता है, वह डिफेक्टिव तो नहीं है । इन अल्फाज के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

شری رشید مسعود : جناب میں

یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ اپنے وعدے میں فیل ہو گئے تو آپ نے آئی - ایم - ایف - لون لینے کی کوشش کی - میں یہ مانتا ہوں کہ کچھہ خاص وجوہات میں آئی - ایم - ایف - سے لون لینا یا اس کے لئے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے - لیکن سرکار کو یہ بھی بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہئے تھا کہ آئی - ایم - ایف - سے لون لینے کے بعد بھی اگر ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکے تو کیا ہوگا - اس لئے آئی - ایم - ایف - سے لون لینے سے بہتر یہ تھا کہ ہم اپنی پلاننگ کو اپنی بجٹنگ کو اپنی مشینری کو درست کرتے - اگر آئی - ایم - ایف - سے لون لینے کے بعد بھی ہم اس دلدل سے نہیں نکلتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے سوائے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا ہے - تمام راستے ہمارے بند ہو جائیں گے - اس لئے ہمیں اپنی پلاننگ کو اپنی بجٹنگ کو اپنی مشینری کو درست کرنا چاہئے - اب تک آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا اور آئی - ایم - ایف - سے لون لینا بہتر سمجھا -

جہاں تک ہمارے فارن ایکسچینج اور فارن ریزرو کا سوال ہے وہ بھی گرتا جا رہا ہے - جب ہم ۱۹۷۷ع میں سرکار میں آئے تھے تو اس وقت ۲۶ سو کروڑ روپئے کے قریب ہمارا فارن

ہندوستانی رہتے ہیں ان سے ہم درخواست کریں کہ وہ اپنے ملک میں انویسٹ منٹ کریں اکونامک ٹائمز کے سروے کے مطابق قریب ۹۰ ہزار کروڑ روپیہ ہمارے ہندوستانی بھائی دوسرے ممالک میں انویسٹ کرتے ہیں - اگر ہماری سرکار اور کافی سمجھ ہوتی تو وہ اس مسئلے پر غور کرتی اور آئی - ایم - ایف - سے لون لینے کے بجائے اپنے ہندوستانی بھائیوں سے جو یہاں سے چلے گئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان سے درخواست کرتی کہ وہ اپنے ملک میں انویسٹ کریں - میں اُمید کرتا ہوں کہ دس بیس پرسینٹ انویسٹ منٹ کرانے میں سرکار کامیاب ہو جاتی - ایک بڑی پرابلم سولو ہو جاتی -

PROF. N. G. RANGA: It cannot be more than hundred crores. You need thousands of crores.

SHRI RASHEED MASOOD: It will be more than 5000 crores, which you have obtained from the IMF.

ہماری ایمبیسیز کی کیا حالت ہے - ودیش میں رہنے والوں کی کبھی گیدرنگ نہیں ہوتی کبھی ان کو بلایا نہیں جاتا کئی بار تو ان کے پاس ان کے نام پتے بھی نہیں ہوتے - میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا - ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آج دیش کی کیا حالت ہے - آج بنگال میں دیکھئے خشک سالی بھی

[شری رشید مسعود]

ریزرو تھا - لیکن جب ہم نے ۱۹۷۹ع میں سرکار کو چھوڑا تو اس وقت ہمارے ملک کے پاس ۵۳ سو کروڑ روپئے فارن ریزرو تھا - یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے باہر یہ کہہ دیا کہ ہم نے فارن ایکسچینج کو فارن ریزرو کو ختم کر دیا جائے ہم نے ملک کو بینکرپٹ کر دیا - یہ آپ کا ہی ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کے مطابق ہم نے ۵۳ سو کروڑ روپئے کا ریزرو چھوڑا تھا - آج آپ کی کیا حالت ہے - آپ کے پاس آج ۳۵ سو کروڑ روپئے کا فارن ریزرو ہے - اس میں بھی ۱۵ سو کروڑ روپئے جو آپ کو آئی - ایم - ایف - کی قسط ملی ہے اس کا ہے - اگر ۳۵ سو کروڑ روپئے میں سے اس ۱۵ سو کروڑ روپئے کو گھٹا دیا جائے تو صرف ۱۹ سو کروڑ روپئے کا فارن ریزرو بچتا ہے - یہ ہے آج کی حالت یہ ہے آج کا فیکٹ جس کے لئے آپ دن رات چلاتے ہیں کہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف جا رہے ہیں - کیا یہ سیلف ریلائنس ہے -

اس کے لئے آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے - بجائے سیلف ریلائنس کی طرف بڑھنے کے آپ نے ملٹی نیشنلس کو انوائٹ کیا آئی - ایم - ایف - اور دوسرے اداروں سے لون لیا - ہم نے کئی دفعہ آپ کو سجیشن دیا کہ دنیا کے ملکوں میں جو ہمارے

فیصلہ کیا - اس پر آپ نے ۱۲۱ سو
کروڑ روپیہ خرچ کیا جس دیش میں
لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی نہ
ہو وہاں تماشے پر اتنا روپیہ خرچ ہو
رہا ہے - خیر اس کو چھوڑیئے لیکن
وہ بجلی جو ہریانہ ، میں ٹیوب ویل
کو ملنی چاہئے وہ اس کسان کو نہ
مل کر جو آپ کو کھانے کے لئے گیہوں
دیتا ہے ایشیاڈ گیمس کے لئے دی
جاتی ہے - کبھی ایسا نہیں ہوا -
ہریانہ کی تاریخ میں ابھی تک
ٹیوب ویلس کے لئے اس طرح سے
بجلی نہیں کاٹی گئی - اس طرف
توجہ دینے کی ضرورت ہے - یو - پی -
میں بھی جہاں خشک سالی ہے وہاں
بھی کسانوں کو ۶ گھنٹے بھی بجلی
نہیں مل رہی ہے - ۱۹۷۷ع سے
۱۹۷۹ع تک جب ہماری گورنمینٹ
تھی اس وقت بھی خشک سالی کا
وقت آیا تھا - لیکن ہم نے سب سے
پہلے یہ فیصلہ لیا کہ بڑے بڑے
شہروں میں بجلی کم دے کر وہ
بجلی دیہاتوں میں کسانوں کو
ٹیوب ویلس کے لئے دی تھی - اس
طرف دھیان دیجئے کہیں ایسا نہ
ہو کہ آج جو ۲۵ لاکھ ٹن گیہوں
کا آیات کیا ہے یہ کہیں ۵۰۰۰ ٹن
نہ ہو جائے - آپ کہتے ہیں کہ سب
ٹھیک ہے لیکن ہمارا کہنا ہے کہ
حالات ٹھیک نہیں ہیں - آسام اور
پنجاب کی بات تو روزمرہ کی ہو چکی
ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں
ہے قحط بھی ہے - وہاں پر پبلک
بہت پریشانی میں ہے - اڑیسہ کی
حالت دیکھئے - وہاں حالات اتنے
خراب ہیں کہ ٹرکس میں جو مال
جاتا ہے اس کو چھین لیا جاتا ہے -
آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا - آپ
کا ڈسٹری بیوشن کا سسٹم بہت ڈیفیکٹو
ہے - آفیسرس جو سامان لے کر جاتے
ہیں وہ بھی ان سے چھین لیا جاتا
ہے - ابھی بہار میں سنتال پرگنہ کا
واقعہ آپ کے سامنے ہے - آپ بھلے ہی
کچھ بھی کہتے رہیں کہ کوئی بات
نہیں ہے لیکن آج دیش کی حالت
بہت خراب ہے - آج ہی ہندوستان
ٹائمس انڈین ایکسپریس میں بہار
اڑیسہ کی حالت کے بارے میں آیا
ہے وہاں بھوک مری ہے - اترپردیش
کے ۲۷ ضلعوں میں خشک سالی ہے -
باقی ضلعوں میں پانی آ گیا ہے -
جہاں خشک سالی ہے وہاں ۴۵ سے
۶۵ فی صدی تک فصلیں تباہ ہوگئی
ہیں اور جہاں سیلاب آ گیا ہے وہاں
۵۰ فیصد اور کہیں کہیں تو مکمل
طور پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں -
بہار یو - پی - بنگال اڑیسہ کی یہ
حالت ہے - راجستھان کے بارے میں
بھی ابھی انہوں نے بتایا - اس طرح
سے ۵-۶ راجیوں کی حالت بہت
خراب ہے - ہریانہ میں حالانکہ
خشک سالی کا اثر نہیں ہوتا ہے -
لیکن اس مرتبہ ہوا ہے - اس کی
وجہ ہے کہ آپ نے ایشیاڈ کرانے کا

بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آپ کے بجٹ میں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرووِیژن رکھ رہے ہیں کہ آپ کا کچھ کنسرن ہے یا آپ پریشان ہیں - آپ کی پلاننگ میں کوئی خاص چینج دکھائی نہیں دیتا - میں چاہوں گا کہ ہمارے منسٹر صاحب بتائیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں - کہنا تو بہت چاہتا تھا لیکن آپ گھنٹی بجا دیتے ہیں اور جو دماغ میں خیالات ہوتے ہیں وہ بھی منتشر ہو جاتے ہیں - صرف ایک بات کہہ کر ختم کر دوں گا ایجوکیشن کے سلسلے میں -

یہاں پر کچھ صاحبان نے کھڑے ہوکر اعتراض کیا بنگال کی سرکار کا - بنگال کی سرکار میری نہیں ہے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ اس سرکار کے لئے لیکن اگر ایجوکیشن میں کوئی امپروومینٹ آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے ایکسپیکٹ کر لینا چاہئے - اگر وہ ویسے ہ ویسا ہی پڑا ہوا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں تو کمپلیمنٹ فیلیور ہو رہا ہے - آج تمام یونیورسٹیز میں ہنگامہ ہے کیونکہ آپکے سسٹم میں ہوتھ میں فرسٹریشن پیدا کر دیا ہے - پہلے پلاننگ میں آپ نے ۷ فیصدی اپنے بجٹ کا رکھا تھا ایجوکیشن پر اور آج ۲ فیصدی خرچ کر رہے ہیں جبکہ اسکے مقابلے میں اب زیادہ

[شری رشید مسعود]

کہنا چاہتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ رورل ری کانسٹرکشن ڈیپارٹمینٹ معلوم نہیں کہاں ورک کر رہا ہے -

رورل ری کانسٹرکشن کی بجائے رورل ڈیولپمینٹ ہو گیا ہے تو بہت ہی اچھا نام ہے - لیکن رورل ڈیولپمینٹ آپ کا کہاں ہے وہ تو ڈیولپمینٹ نہیں کر رہا ہے - ہمیں یاد ہے آپ کسی بھی دیہات میں چلے جائیں- سنہ ۱۹۷۷ع سے ۱۹۸۰ع کے درمیان کچھ سڑکیں بنی ہیں فوڈ فار ورک کے ڈیپارٹمینٹ کے نام سے - لہذا ضرورت آپ کو اس بات کی پیش آئی کہ اس کا فائدہ جنتا والے نہ اٹھائیں اور اس لئے اس کا نام بدل دیا جائے - نام بدل دیتے اور کام وہی رہتا تو ہمیں شکایت نہ ہوتی اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے - لیکن آپ نے نام بدلنے کے ساتھ ساتھ کام بھی بدل دیا کیونکہ آپ کی نیت دیہات میں کچھ کام کرنے کی نہیں ہیں - لہذا آپ کسی بھی دیہات میں چلے جائیں - آپ کی گورنمینٹ کو ڈھائی تین سال ہو گئے ہیں - جہاں ایک کلو میٹر کی سڑک بھی بنی ہوئی ہے وہاں چلے جائیے - جتنے مزدور سڑک بنانے میں لگائے جاتے تھے ان کو ہی اناج دیا جاتا تھا لیکن آپ نے سب بند کر دیا ہے -

جیسا میں نے بتایا سوکھے کی حالت ہے اس میں ہر آدمی کو ز

ضرورت ہو گئی ہے - کس طرف آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں -

آپ کنسیشن دینا چاہتے ہیں - جب بھی آپکا بجٹ میں ریلیف آیا تو کنسیشن کس کو ملا - انڈسٹریلیسٹ کو اس مرتبہ کسکو ملا - انڈسٹریلیسٹ کو - آئندہ کسکو ملے گا انڈسٹریلیسٹ کو - اس ملک کے غریب کے لئے تعلیم ضروری ہے لیکن آپ ایجوکیشن کے بجٹ کو دن بدن گھٹاتے جا رہے ہیں - میں صرف بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپکو سسٹم کے بارے میں بھی سوچنا پڑیگا کہ آپ اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں -

ہم پارلیامینٹری فورم آف یونیورسٹیز اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک کنوینشن فروری میں کرنے جا رہے ہیں - اس میں آپ سبھی لوگوں کو دعوت ہے اس میں مدد کریں اور دیکھیں - وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فارمولا نکالا جائے کہ ایجوکیشن سسٹم میں کیا خرابی ہے اور کیا کیا امپروومینٹ کیا جائے - یہ چند چیزیں آپکو بتائیں - چونکہ ٹائم کم ہے اس لئے آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ آپکی پلاننگ تو ڈیفیکٹو نہیں ہے اور آپکا سسٹم جو اسکو امپلی مینٹ کرتا ہے وہ ڈیفیکٹو تو نہیں ہے - ان الفاظ کے ساتھ میں سماپت کرتا ہوں -

SHRI CHITTA BASU (Barasat): I want to seize this opportunity to draw the attention of the Government, and also of the House to a very perennial problem that relates to Centre-State financial relations. These supplementary Demands for Grants have a very large sums for transfer to the States. Naturally, it gives me an occasion when I can draw the attention of the Government regarding Centre-States financial relations. As I do not have much time to discuss in detail these very important aspects of our national life, I would only refer to certain important aspects of it so that the points can be driven home.

Now, as you know, the Government of India have taken a decision for converting all the over-drafts of the States into medium-sized loan upto March 31st, 1980. Now, all the overdrafts have been converted into medium term loan; and from the First of July, 1982, there will be no overdraft for any State; but, at the same time, a decision has been taken that the amount of overdraft which has been drawn from January to 31st March, this year, will have to be paid by the State exchequer during this current year, that is, for the rest of the nine months, the State will have to mobilise some resources which can enable them to repay the Government of India the three months overdraft, in addition or apart from the expenditure they are likely to incur for the remaining nine months of the year. I would only appeal to the Government that, in view of the fact that there have been widespread floods causing damages necessitating the State Governments to undertake huge relief operations massive relief operations without any opportunity of drwing the overdrafts from the RBI, is it possible for the State Governments to make the payment of three months overdraft for the current year? Even if we go through these documents, we will find that under the accounts of transfer to the States,

[Shri Chitta Basu]

only Rs. 75 crores have been earmarked for the cyclone affected relief. No mention has been made for the drought relief. As a matter of fact, may I presume that the Government of India is also coming with the proposal of another supplementary grant to meet the situation arising out of the drought conditions in our country? It is very clear that only Rs. 75 crores have been earmarked for the relief operation of the drought and cyclone victims; nothing has been mentioned or allocated for drought relief. Therefore, I think the Government has not given full consideration to the drought problems in our country. As a matter of fact, it is quite well-known to you and to the House that several State Governments have asked their claims for huge sums of money. Orissa has claimed more than Rs. 600 crores. Rajasthan has claimed more than Rs. 100 crores. West Bengal Government has claimed more than Rs. 100 crores. If you go through these figures, it will come to about Rs. 1000 crores which the States require today to meet the situation arising out of the drought conditions prevailing in the country. Unfortunately, these documents provide that of the total fund transferred to the States, only Rs. 75 crores have been earmarked for relief of the drought and cyclone affected people; nothing, not a single pie has been allocated for drought. This means, this shows, this betrays, this exhibits the callousness of the Government; the Government does not give a proper thought to the situation that is developing in our country. Therefore, I want to drive home this point that the Government is callous, the government is indifferent and the government cannot have a comprehensive view of the problem the country is facing today, particularly arising out of drought.

What is the necessity of overdrafts? There is no limit to your deficit financing ; the Central Government has got no limit for the deficit financing. As a matter of fact, for the last 3 year, on avarage deficit financing has been of the order of Rs. 2000 crores. During the three years, you have a deficit financing of Rs. 6000 crores; and you are very much angry with the States when they have to resort to deficit financing and overdrafts from the RBI. But it is your fiscal policy, it is the inflation which rises the cost of the expenditure of the State Governments. It is needless to explain in detail; you know everything. Therefore, the fundamental fault lies with you in your fiscal and economic policies out of which inflation grows and the impact of it falls on the States. They are bound to resort to overdrafts. You stop overdrafts; you do not provide them adequate financial assistance to meet the contingency. You mean to say that it is only the Central Government that have got role to play and the State Governments have got no role to play or the State Governments have got no responsibility towards the people of the States. If that is your attitude, then our country is not a quasi-federal; it is a unitary form of Government. This is a very basic and fundamental issue and this is one of the reasons which has led to the discontent in the Punjab, whatever might be the law and order situation; whatever might be the other situation, but the fundamental question is the financial relation between the Centre and the States in which you take pride that you are transferring resources from the Centre to the States; and that also I have explained what is the tiny amount that you have given.

The West Bengal Plan is only of the order of Rs. 531 crores for the year 1981-82; and this is exactly what it was, what was the expenditure incurred by the West Bengal Government last year. Having regard to the cost escalation, the plan size of West Bengal is lower; and having regard to the fact that this Rs. 531 crores size of plan includes certain special programmes in the

drought affected areas, which cost also about Rs. 15 crores, therefore, the plan has been pruned, the plan has been reduced. May I request the hon. Minister to reconsider it so that the plan size of the West Bengal may be revised and so raised so that the development tempo in the State can be further continued.

Lastly, there is an injustice done regarding market borrowing. The Central Government can raise any amount of fund by borrowing not ony from within this country but outside also. The State Governments have got no scope of borrowing from outside. During 1961—66, the total market borrowings of the Central Government and the States was of the order of Rs. 823 crores. What was the apportionment? The States' share was 62.7 per cent—about Rs. 516 crores; the Centre's share was 37.3 per cent—about Rs. 307 crores. The States' share was bigger whereas the Central Government's share was less. What comes there during the Sixth Five Year Plan? My hon. friend here was the former Chairman of the Finance Commission.

During these Sixth Five Year Plan, 1980—85, the total market borrowing is contemplated, or is expected to be of the order of Rs. 20,000 crores. The Centre's share is 75 per cent or Rs. 15,000 crores and the States' share is 25 per cent or Rs. 5,000 crores. What are you planning for? Are you planning to kill States? Are you planning to deprive the States of thier financial resources? That is enough and I need not state more facts to prove that your attitude is financially to have a unitary type of Government whereas the Constitution provides or enivsages a quasi-federal Government.

I have not got much time. But I would only implore upon the Government to revise this policy, in the interests of the unity and integrity of the country to satisfy the hopes and aspirations of the people of the States. Sir, you also represent the States. The people in the States expect much from the State Governments. You are beyond their reach. But I am within their reach. The resources of the State Governments are static and non-elastic, whereas the demands of the people on the States are elastic. Your resources are extraordinarily elastic and the demands on you are not as strong as that of the people of the State Governments. Therefore, do not treat the State Governments as beggars at your door. Do not treat them as mere municipalities. Give them more financial powers. I hope that the points which I have raised would receive due consideration of the Government.

MR. CHAIRMAN: Before I call Shri Ramavatar Shastri, I would like to remind that the time allotted for this was two hours and we have already taken more than two hours. So, I would appreciate if you could kindly restrict your speeches—shall I say--to five to seven minutes each?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: You can extend the time.

AN HON. MEMBER: Time should be extended.

MR. CHAIRMAN: Besides, Shastriji is wanted some where else. We have two other Bills also.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, सरकार ने 589.70 करोड़ रुपए के अनुदानों की मांग की है । इसमें 30 मांगें शामिल हैं । मैं दो तीन मांगों के सिलसिले में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा ।

मांग संख्या 41 में प्राकृतिक विपत्तियों की बात कही गई है। उसमें बाढ़ और चक्रवात की चर्चा है, लेकिन सुखाड़ या अकाल की चर्चा नहीं है। आज हमारे देश के करीब एक दर्जन राज्य बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित हैं। सब से

[श्री रामावतार शास्त्री]

ज्यादा खराब स्थिति उड़ीसा, बिहार पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसम की है । और भी राज्य हैं, जहां कहीं कहीं स्थिति ठीक नहीं है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात आदि हैं । इन सभी राज्यों में स्थिति बड़ी दयनीय है ।

अभी यह ठीक ही कहा गया है कि सरकार ने बाढ़ और चक्रवात के नाम पर 75 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है, लेकिन इसके लिए हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता हो सकती है, और हैं, और कई राज्यों ने ज्यादा से ज्यादा मांग भी की है । उड़ीसा में चक्रवात, बाढ़ और सुखाड़ तीनों है, वहां के लोग तीनों बीमारियों से पीड़ित हैं । वहां 70 प्रतिशत धान की फसल नष्ट हो चुकी है, उद्योग-धंधे ठप्प हैं, क्योंकि बाढ़ और चक्रवात के कारण बिजली की व्यवस्था नष्ट हो चुकी है । चक्रवात और बाढ़ की वजह से 13 हजार 210 हैक्टेयर भूमि में बालू भर गया और लगभग 3.84 लाख हैक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो चुकी है । और भी वहां काफी हानि हुई है और आंकड़ों के जरिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह की स्थिति चलने से वहां पर राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए परेशानी हो रही है और उसमें उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है । क्योंकि उसको बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

पश्चिमी बंगाल में 15 जिलों में से 13 जिले बुरी तरह से सुखाड़ की चपेट में हैं । धान के लगभग 70 फीसदी पौधे पानी न मिलने के कारण सूख गए हैं । इस के पहले भी वहां पर सुखाड़ की स्थिति रही है । हर साल वहां पर तीन फसल होती हैं, लेकिन इस बार केवल एक फसल ही हुई है और दो फसलें मारी गई हैं । सूखे से सहायता के रूप में वहां की सरकार ने आपसे 72 करोड़ रुपया मांगा था, जब कि आपने उसे 24 करोड़ रुपया ही दिया है । इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहां पर कैसी स्थिति होगी ।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, वहां पर 33 जिले और 587 प्रखण्ड हैं, जिनमें से 450 प्रखण्डों में सूखा और बाढ़ का प्रकोप है और वहां की 80 प्रतिशत आबादी पीड़ित है । वहां की आबादी 7 करोड़ से भी ज्यादा है । वहां पर 1982–83 का प्रोडक्शन का टार्गेट 120 लाख टन अनाज का था, लेकिन उसमें बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति के कारण बहुत कमी आ जाएगी । पिछले साल 1981–82 में वहां पर अनाज उत्पादन का लक्ष्य 116 लाख टन का था लेकिन उसके मुकाबले में 95 लाख टन ही पैदावार हुई । इसका मतलब है कि 21 लाख टन पिछले साल भी वहां उत्पादन में कमी रही । इन आंकड़ों से आप वहां की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं । कम उत्पादन के कारण वहां पर आवश्यक वस्तुओं के दामों में तेजी आ गई है । जिस चावल की कीमत वहां पर पहले 3 रुपये किलो होती थी, आज वही चावल चार और साढ़े चार रुपये किलो बिक रहा है। खुद गेहूं की कीमत में 75 रुपये क्विंटल का इजाफा हो गया है । उसका कारण सिर्फ कम पैदावार का होना, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति होना है, जिसके कारण वहां की फसल मारी गई हैं । स्थिति का फायदा गल्ला चोर और मुनाफा खोर उठा रहे हैं । उन्होंने बीजों के दाम बढ़ा दिए हैं । दालों के दाम प्रति किलो

डेढ़ रुपये ज्यादा हो गए हैं । इन सब चीजों से आप वहां की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं । इन तामाम बातों पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार ने आपसे 236 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है । परन्तु आपने बजट में 75 करोड़ रुपया ही मांगा है । आप क्यों उसको उतना पैसा नहीं देते, जितना वह मांग रहा है । इसके अलावा उनकी गल्ले की मांग एक लाख 5 हजार टन है, जिसमें से आप 20 हजार टन चावल और 20 हजार टन गेहूं उसको दे रहे हैं । इतने से कैसे वहां की अकाल की स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा । मैं यहां पर रोज सुनता हूं कि बिहार में भूख से मौतें हो रही हैं । संथाल परगना और छोटा नागपुर जिलों के 4 लाख लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, पंजाब में आ गए हैं और पंजाब में भी उनको सताया जा रहा है । उनके पास टिकट होते हुए भी, बगैर टिकट करार देकर जेलों में डाला जा रहा है । वहां से दूसरों की सेवा करने के लिए 4 लाख लोग बाहर चले गए हैं । वहां पर एक स्थान पर गोलियां चलाई गई, जब वे एक भूख मार्च कर रहे थे, जिसके कारण 7 लोग मारे गए । लेकिन वहां के जो वर्तमान संसद सदस्य श्री शिबु सोरन हैं, उनका कहना कि उस गोलीकांड में 17 आदमी मारे गए हैं और वहां भूख से मरने वालों की संख्या 100 से भी अधिक है । यह उनका कहना है, जो कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चो से सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन वहां के मुख्य मंत्री दिल्ली से बयान दे देते हैं कि कोई भी आदमी वहां भूख से नहीं मरा । लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं । वहां के चीफ मिनिस्टर यहां पर अर्बन कोआपरेटिव बैंक के घोटाले के सिलसिले में बैठे हुए हैं, जब कि उनको वहां पर होना चाहिए । वह तो उनके और लोग देख सकते थे.....

MR. CHAIRMAN: Is it relevant to this debate?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: This is very much relevant. People are starving and he is sitting over here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): Everything under the sky is relevant!

श्री रामावतार शास्त्री : इसीलिए वहां की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, चाहे वह बंगाल का इलाका हो या बिहरा का, उड़ीसा हो या राजस्थान का क्षेत्र हो । वैसे राजस्थान के बारे में यहां पर काफी कहा जा चुका है और मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं । मेरा मत है कि आप उन सरकारों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दें, आर्थिक रूप से भी और अनाज के रूप में भी, ताकि वे अकाल की स्थिति का सामना कर सकें । अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो दिक्कत होगी । मैं संथाल परगना की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं-- इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद काम्यूनिस्ट विधायक श्री विशेश्वर खां ने बताया कि नाला, कुडहित प्रखण्ड में रोज एक दो व्यक्ति भूख से मरने लगे हैं । कुछ दिन पूर्व तक निम्न वर्गीय मजदूर ही भूख के शिकार हो रहे थे, किन्तु अब उच्च मध्यम वर्ग के किसान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं । जिस परिवार के बारे में लोग कल्पना भी नहीं करते थे, वे आज मिट्टी काटने का काम खोज रहे हैं, किन्तु सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य "ऊंट के मुंह में जीरे सरोखा" साबित हो रहा है ।

[श्री रामावतार शास्त्री]

इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति कितनी दयनीय है।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसाय) : ड्राउट पर आप बोले हैं। इस पर क्या करेंग ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस पर आपको भी बोलना चाहिए । नहीं तो बिहार वाले कहेंगे कि जब शास्त्री जी बोल रहे थे तो कृष्णा साही बीच में रोक रही थी । इसलिए मत बोलिए।

श्रीमती कृष्णा साही : इलेक्शन आने पर देखा जाएगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : इलेक्शन से पहले ही बात हो जाएगी । इलेक्शन की आप क्यों चिन्ता कर रही हैं । आप भी रहिएगा और दूसरे लोग भी रहेंगे । जब आपको मौका मिले, तो आप कहिए। मैं आपको कभी बीच में नहीं छेड़ता हूं। अगर मैं छेड़ना शुरू कर दूं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : शास्त्री जी क्या आप छेड़ लेते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय, बम्बई कारखाने की हड़ताल के सिलसिले में त्रिपक्षीय समिति बनाई गई है, उस हड़ताल को नौ महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 18 जनवरी से हड़ताल हुई थी । कई बार हम लोग बहस कर चुके हैं, इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को बुद्धि से काम लेना चाहिये । हर बार दिमाग को टु-लेट करके काम नहीं चलता है । वहां के झगड़े को सरकार तय करे। नौ अरब से ज्यादा रुपये की क्षति हो चुकी है, अभी भी इसको बचाया जा सकता है। हड़ताल को समाप्त करने के लिये सरकार को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिये और उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए । यदि मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कह सकें, तो उनको जवाब देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं सप्लीमेन्टरी डिपाण्ड्स फौर ग्रान्ट्स को रिपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसका समर्थन करते हुए मैं चन्द बातें अपने इलाके के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं ।

सबसे पहले मैं डिमाण्ड नं० 2—एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में दो एसेंबली के सैगमेंट है—लेह और कारगिल। बदकिस्मती से लेह क्षेत्र में बुद्धिश्ट की मजोरिटी है और कारगिल में मुस्लिम मजोरिटी है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कारगिल सैक्टर में डैजर्ट डवेलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा था, पांच ब्लाक्स में, उनमें से चार में इसको विदड्रा कर लिया है। जिसको देखने में ऐसा लगता है कि यह काम्यूनल लाइन पर करने का शुबाह हो सकता । इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि इस की फ़ौरी तौर तबज्जह देनी चाहिए और जो चार ब्लाक्स में कार्यक्रम बन्द किया गया है, उसको रिस्टोर करना चाहिये । जसा कि बताया गया है कि वहां लेह के मुकाबले में रेनफ़ाल ज्यादा है और ग्रीनरीज ज्यादा है। आपने एक टीम टास्क फ़ार्स ड्राउट-प्रांमो एरियाज प्रोग्राम और डजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के लिये भेजी है, उनकी सिफ़ारिश है, कि वहां पर ज्यादा रेनफ़ाल होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐवरेज

हार्डली दस-बारह सेंन्टीमीटर रेनफ़ाल है। आप अन्दाजा लगाइए कि यहां एक-एक घंटे में 20–20 सेंन्टीमीटर रेनफ़ाल होता है, जब तेज बारिश होती है। जबकि वहां सिर्फ़ 10–12 सेन्टीमीटर होती है। इसलिये मेरी आप से गुजारिश है कि इन सब सिचुएशन को देखकर आपको इस मामले में तबज्जह देनी चाहिये। और जिन चार-चार ब्लाक जिला कारगल में इस प्रोग्राम की अमलंदारी रोक दी है फिर से बहाल किया जाये।

दूसरी बात मैं डिमांड नं0.14– काम्यूनिकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। आपको पता है कि सैटेलाइट काम्यूनिकेशन सिस्टम चल रहा है। आपने टेलीफोन काम्यूनिशकेशन सिस्टम मुल्क में पांच स्टेशन पर शुरू किया है। जिसमें एक लेह है, आईजल है, पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप है और पांचवा शायद गुजरात में है। पांच में से मुझे पता नहीं है कि किसकी क्या पोजीशन है। लेकिन जहां तक लेह का सवाल है, जब यहां से टेलीफोन कांल बुक की जाती है तो कभी लाइन मिलती ही नहीं है। पहले तो एक्सचेंज मे जो मैम साहब बैठी होती है उनको एजुकेट करना पड़ता है कि लेह कहां है। जब कहीं जाकर मुश्किल से लाइन मिलती है, तो कहा जाता है लेह एक्सचेंज से रिस-पास नहीं मिल रहा है। जब लेह से दिल्ली के लिये मिलाई जाती है, तो कहा जाता है कि दिल्ली से कोई रिसपास नहीं मिल रहा है। हायर अथारिटीज को कई बार लिखा है। मुझे पता नहीं है कि क्या हालत है, इसलिए इस तरफ भी आपको तवज्जह देनी चाहिये वायर लैस टेलीग्राफ भी लेह में मुश्किल से महीने में दस दिन चलती है। पैसा पूरा ले लिया जाता है तार को डिसपैच बा-डाक करते हैं। इसके लिये कौन जिम्मेदार है लेह और कारगिल का टेलीफोन एक्सचेंज है, उसको एटोमैटिक बनाया जाये, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा है कि 24 घंटे वहां काम करना मुश्किल होता है। पहले कहा गया था कि कन्टेनराइज इलैक्ट्रा-निक एक्सचेज वहां पर डाल रहे है। दो साल हो गए है, पता नहीं आप कब इसको करेंगे मेरी कांस्ट्रीचयून्सी में चन्द एक नई पोस्ट आफिस के लिये भी आपसे मांग की गई थी। वहां दो क्षेत्र नौबराह और जानस्कार ऐसे है, तो छः, सात महीने लेह और कारगिल हैडक्वार्टर से कट-आफ रहते हैं। वहां पर सब-पोस्ट आफिस बनाया जाए। ब्रांच पोस्ट आफिस चलता हैं, सब पोस्ट आफिस नहीं बन रहा है। इसकी वजह से खसूसी तौर से पैंशनर्स को परेशानी होती है। कट आफ होने की वजह से छः महीने के बाद पैंशन लेने जाना पड़ता है। इस लिये इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। लेह पोस्ट आफिस में जितने भी पार्सल जाते है, वहां बहुत चोरी होती है। अभी तक कोई इंक्वारी नहीं हुई है। बहुत से लोगों को पार्सल नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि कोई आर्गानाइजड् गेंग है जो हो सकता है लेह में है या जहां से पार्सल रवाना होते हैं वहां से गायब होते हैं। इसको देखने की जरूरत है।

इसी तरह से टेलीफोन बिल जो गलत आ जाते हैं, इस तरफ़ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी पिछले दिनों मेरे बिल में 3–4 ट्रंक-काल सिल्चर आसाम के लिये दिखाए गए। मैंने जब पूछा तो बताया गया कि यह आपके ही टेलीफोन नम्बर से बुक किये गए हैं, जबकि सिल्चर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार जब बहुत सारे एम० पीज दिल्ली में नहीं होते है, उस पोरिपड के बिल भी आ जाते हैं। इन सब चोजों को देखने की आवश्यकता है।

[श्री पी० नामग्याल]

ग्रांट नंबर 26 के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। 1978-79 में सेंट्रल स्कूल लेह के लिये सेंक्शन किया गया था, क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के आफिसर्स और सर्विस मैन आर्मी के रहते हैं। पहले यह सोचा गया था कि कोई जगह किराये पर मिल जाएगी, लेकिन यहां से जो भी पत्र जाते है, स्टेट गवर्नमेंट उसका जवाब देती नहीं है। यहां से किसी भी सिलसिले में जानकारी चाही जाये, स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं देती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सिलसले में किसी मिनिस्टर को यहां से जाना चाहिये और मामले की जांच करके कोई न कोई हल शीघ्र निकालना चाहिये ताकि वहां बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल सके। नहीं तो वहां पर कोई आफिसर जाने को तैयार नहीं होता है। इस तरफ तबज्जह देने की जरूरत है।

डिमांड नंबर 30 पावर प्रोजेक्टस के बारे में है। मेरा सजेशन है कि मेरी कांस्टीटवेंसी लद्दाख में हाईड्रो-इलेक्ट्रिक के बहुत सारे पावर पोटेंशियल मौजूद हैं। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीमें अपने हाथ में लेनी चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। स्तकना में साढ़े तीन करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट बनना था, जिसकी लागत अब 20 करोड़ पर पहुंच गई है, अभी तक पता नहीं है कि वह कब तक बनेगा। इसी प्रकार दोमखार प्रोजेक्ट पता नहीं कब से चल रहा है और सुरू प्रोजेक्ट करगिल जिले में है जो बहुत ही पावर पोटेंशियल माना गया है। पता नहीं इसमें कितने साल लगेंगे। जबकि हमारे बीस नूकाती प्रोग्राम में छोटे छोटे बिजली प्रोजेक्ट को अहमीयत दिया गया है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

इसी प्रकार एक और चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं लेह में स्माल काइंस नहीं मिलते है। दुकानदार माचिस और मिठाई के जरिये ट्रांजिक्शन करते है। स्टेट बैंक वालों का कहना है कि चेस्ट नहीं है। इसलिये मेरी खुसुसी तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि कम से कम इस क्षेत्र के लिये चेस्ट की व्यवस्था की जाए। हमारे यहां की कुल आबादी एक लाख तीस हजार है। ज्यादा चेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ तो वहां पर अवश्य भेजें, जिससे वहां के निवासिपों को इस तरह को कठिनाई न हो।

वहां जो मरकजी सरकारी मुलाजिम तबके हैं, उनको अब जो अलाउन्सेज हैं या विन्टर अलाउन्सेज है स्टेट गवर्नमेंन्ट के मुकाबले में बहुत ही कम है। मैंने फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से टेक-अप किया था। नतीजा यह है कि जितने भी आफिसर्स हैं, वे वहां जाना नहीं चाहते हैं, कोई न कोई बहाना करके या कभी मेडिकल लीव लेकर चले जाते है और काम आपका वहां ठप्प हो जाता है तो उसके लिये फैसिलिटीज आप दीजिये।

लेह में जो कॉस्ट आफ लिविग है, वह श्रीनगर से 100 परसेंट ज्यादा है। मैंने रेडियों स्टेशन का केस लिया था उनके अलाउन्सेज का। दिल्ली, शिमला और श्रीनगर में ज्यादा तनख्वाह पाते है, लेह में कम मिलते है तो क्यों वहां जाएं। स्टेशन डायरेक्टर की पोस्ट कई महीनों से खाली पड़ी है। इसी तरह से जो पोस्ट आफिस है या जो दूसरे सेंट्रल गवनमेंट के इदारे हैं उनमें बहुत सारी पोस्ट्स खाली है। कोई अच्छा आफिसर जाने के लिये तैयार नहीं होता है इसलिये आपको अलाउन्सेज बढ़ाने की जरूरत है।

मैं ब्राडकास्टिग पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। वहां एक ही स्टूडियो है, रेडियो के लिये। उसमें, आर्टिस्ट को लाईन में बैठना पड़ता है कभी म्यूजिक का होता है, कभी ड्रामे का और कभी कुछ होता है। स्टूडियों सिर्फ़ एक है, हमने कहा था कि दूसरा स्टूडियो बना दीजिये अभी तक इस तरफ़ कोई कदम नहीं उठाया गया है। इक्वीपमेंट आपके पास वहां नहीं है। एक छकड़ा सा जीप है जो वहां के मुलाजिम लोग हैं उनको काम करने के लिये, और तो और वहां लैट्रीन तक नहीं है। पिछली दफ़ा मैंने इस सिलसिले में एक क्वेश्चन पूछा था तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि भई जो सामने स्टाफ क्वाटर्स हैं वहां जाना चाहिये। बाहर से जो आर्टिस्ट आयेंगे दूसरों के रेजीडेन्स में स्कवेटिंग के लिये जायेंगे, यह तो बड़े अफ्सोस की बात है। वहां पर कम से कम लैट्रीन की बहुत जरूरत है क्योंकि वह एक रेडियो स्टेशन है, उसके लिये होनी चाहिये। यह शर्म की बात है इंफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिग मिनिस्ट्री के लिये। इसी तरह मानिटरींग इक्वीपमेंट नहीं है न्यूज के लिये। न्यूज को मानिटरींग करना पड़ता है, आल इंडिया रेडियो को टेप करो, श्रीनगर रेडियो को टेप करो, ट्रान्सलेट करो और फ़िर ब्राडकास्ट करो। न्यूज एडीटर के लिये टेलीफोन तक नहीं है। मैं जो पाइंट्स आपके नोटिस में ला रहा हूं, इनको बहुत सीरियसली देख लेना चाहिये। इन चन्द अल्फ़ाज के साथ जो आपने ग्रान्ट्स पेश की है उसका सपोर्ट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो पाइंट्स मैंने रेज किये हैं, वह कन्सर्न मिनिस्ट्री को भेज देंगे।

16 hrs.

شری پی - نام گیال (لداخ) :

سبھا پتی مہودے - میں سپلیمنٹری ڈیمانڈس فار گرانٹس کو سپورٹ کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں - اسکا سمرتھن کرتے ہوئے میں چند باتیں اپنے علاقے کے بارے میں آپکے سامنے رکھنا چاہتا ہوں -

سب سے پہلے میں ڈیمانڈ نمبر ۲ ایگریکلچر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نرواچن چھیتر میں دو اسمبلی کے سیگمینٹ ہے - لیہہ اور کارگل بدقسمتی سے لیہہ چھیتر میں بدھسٹ کی میجورٹی ہے اور کارگل میں مسلم میجورٹی ہے - ایسی حال ہی میں سینٹرل گورنمینٹ نے جو کارگل سیکٹر میں ڈیزرٹ ڈیولپمینٹ کا کاریہ کرم چل رہا تھا پانچ بلاکس ہیں ان میں سے چار میں اسکو ودھڈرہ کر لیا ہے - جس کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کمیونل لائن پر کرنے کا شبہ ہو سکتا ہے - اس لئے میرا سرکار سے آگرہ ہے کہ اس کی طرف فوری طور پر توجہ دینی چاہئے اور جو چار بلاکس میں کاریہ کرم بند کیا گیا ہے اسکو ریسٹور کرنا چاہئے - جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہاں لیہہ کے مقابلے میں رین فال زیادہ ہے اور گلیشیرز زیادہ ہے - آپ نے ایک ٹیم ٹاسک فورس آف ڈراوٹ پران ایریاز پروگرام اور ڈیزرٹ ڈیولپمینٹ پروگرام کے لئے بھیجی ہے انکی سفارش ہے کہ وہاں پر زیادہ رین فال ہوتا ہے - میں کہنا چاہتا ہوں کہ

[شری پی - نام گیال]

وہاں پر ایوریج ھارڈلی دس بارہ سینٹی میٹر رین فال ہے - آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں ایک ایک گھنٹے میں ۲۰-۲۰ سینٹی میٹر رین فال ہوتا ہے - جب تیز بارش ہوتی ہے - جبکہ وہاں صرف دس بارہ سینٹی میٹر ہوتی ہے - اسلئے میری آپ سے گذارش ہے کہ ان سب سچویشن کو دیکھ کر آپ کو اس معاملے میں توجہ دینی چاہئے اور جن چار بلاک ضلع کرگل میں امر. پروگریم کی عملداری روک دی ہے پھر سے بحال کیا جائے -

دوسری بات میں ڈیمانڈ نمبر ۱۴ کمیونیکیشن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں - آپکو پتہ ہے کہ سیٹ لائٹ کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے - آپ نے ٹیلیفون کمیونیکیشن سسٹم ملک میں پانچ اسٹیشن پر شروع کیا ہے جس میں ایک لیہہ ہے اڑل ہے - پورٹ بلیر ہے لکش دیپ ہے اور پانچواں شاید گجرات میں ہے - پانچ میں سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے - لیکن جہاں تک لیہہ کا سوال ہے جب یہاں سے ٹیلیفون کال بک کی جاتی ہے تو کبھی لائن ملتی ہی نہیں ہے - پہلے تو ایکسچینج میں جو میم صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ لیہہ کہاں ہے - جب کہیں جا کر مشکل سے لائن ملتی ہے تو کہا جاتا ہے لیہہ ایکسچینج سے رسپانس نہیں مل رہا ہے - جب لیہہ سے دلی کے لئے ملائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دلی سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے - ہائر آتھوریٹیز کو کئی بار لکھا ہے - مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا حالت ہے اس لئے اس طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہئے -

وائر لیس ٹیلی گراف بھی لیہہ میں مشکل سے مہینے میں دس دن چلتی ہے - پیسہ پورا لے لیا جاتا ہے تار کو ڈسپیچ لیٹ کرتے ہیں - اس کے لئے کون ذمہ دار ہے -

لیہہ اور کارگل کا ٹیلی فون ایکسچینج ہے اس کو آٹومیٹک بنایا جائے کیونکہ وہاں کا موسم ایسا ہے کہ ۲۴ گھنٹے وہاں کام کرنا مشکل ہوتا ہے - پہلے کہا گیا تھا کہ کنٹینرائز الیکٹرانک ایکسچینج وہاں پر ڈال رہے ہیں - دو سال ہو گئے ہیں پتہ نہیں آپ کب اس کو کریں گے -

میری کانسٹی چیونسی میں چند ایک نئی پوسٹ آفس کے لئے بھی آپ سے مانگ کی گئی تھی - وہاں دو چھتر نوبراہ اور زانسکار ایسے ہیں جو چھ سات مہینے لیہہ اور کارگل ھیڈ کواٹر سے کٹ آف رہتے ہیں - وہاں پر سب پوسٹ آفس بنایا جائے - برانچ پوسٹ آفس چلتا ہے سب پوسٹ آفس نہیں بن رہا ہے -

میں سینٹرل اسکول لیہہ کے لئے سلکشن کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر سینٹرل گورنمینٹ کے آفیسرس اور سروس مین آرمی کے رہتے ہیں - پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ کوئی جگہ کرایہ پر مل جائے گی لیکن یہاں سے جو بھی پتر جاتے ہیں اسٹیٹ گورنمینٹ اس کا جواب دیتی نہیں ہے - یہاں سے کسی بھی سلسلے میں جانکاری چاہی جائے اسٹیٹ گورنمینٹ جواب نہیں دیتی ہے اس لئے میرا نویدن ہے کہ اس سلسلے کسی منسٹر کو یہاں سے جانا چاہئے تاکہ وہاں بچوں کو پڑھائی کی سودھا مل سکے -

ڈیمانڈ نمبر ۳۰ پاور پروجیکٹس کے بارے میں ہے - میرا سجیشن ہے کہ مغربی کانسٹی چوینسی لداخ میں ہائڈرو الکٹرک کے بہت سارے پاور پوٹینشیل موجود ہیں - وہاں پر سینٹرل گورنمینٹ کو اسکیمیں اپنے ہاتھ میں لینی چاہئیں - اسٹیٹ گورنمینٹ کے بھروسے نہیں بیٹھنا چاہئے - اسکتا میں ساڑھے تین کروڑ کا ایک پاور پروجیکٹ بنتا تھا جس کی لاگت اب ۲۰ کروڑ پر پہنچ گئی ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کب تک بنے گا - اسی پرکار دوم کھار پروجیکٹ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے او. سورو پروجیکٹ کارگل ضلع میں ہے جو بہت ہی پاور پوٹینشیل مانا گیا ہے - پتہ نہیں اس میں اس کی وجہ سے خصوصی طور پبلشرس کو پریشانی ہوتی ہے - کٹ آف ہونے کی وجہ سے چھہ مہینے کے بعد پبلشن لیٹے جانا پڑتا ہے - اس لئے اس کی ویوستھا ہونی چاہئے -

لیہہ پوسٹ آفس میں جتنے بھی پارسلس جاتے ہیں وہاں بہت چو ہوتی ہے - ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے - بہت سے لوگوں کو پارسلس نہیں ملے ہیں - ایسا لگتا ہے کہ کوئی آرگنائزڈ گینگ ہے جو ہو سکتا ہے لیہہ میں ہے یا جہاں سے پارسلس روانہ ہوتے ہیں وہاں سے غائب ہوتے ہیں - اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے -

اسی طرح سے ٹیلیفون بل جو غلط آ جاتے ہیں اس طرف بھی دھیان دینے کی آوشیکتا ہے - ابھی پچھلے دنوں میرے بل میں تین چار ٹرنک کال سلچر آسام کے لئے دکھائے گئے - میں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ہی ٹیلیفون نمبر سے بک کئے گئے ہیں جب کہ سلچر سے میرا کوئی سمبندھ ہی نہیں ہے - اسی پرکار جب بہت سارے ایم پیز دلی میں نہیں ہوتے ہیں اس پیریڈ کے بل بھی آ جاتے ہیں - اس سب چیزوں کو دیکھنے کی آوشیکتا ہے -

گرانٹ نمبر ۲۶ کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں - ۱۹۷۸-۷۹ع

[شری پی - نام گھال]

نہ کوئی بہانا کرکے یا کبھی میڈیکل لیو لیکر چلے جاتے ھیں اور کام آپکا وھاں ٹھپ ھو جاتا ھے تو اسکے لئے خود لیٹیز آپ دیجئے -

لیہہ میں جو کاسٹ آف لیونگ ھے وہ شری نگر سے ۴۰۰ پرسینٹ زیادہ ھے میں نے ریڈیو اسٹیشن کا کیس لیا تھا انکے الاونسز کا - دلی شملہ اور سرینگر میں زیادہ تنخواہ پاتے ھیں لیہہ میں کم ملتے ھیں تو کیوں وھاں جائے - اسٹیشن ڈائریکٹری کی پوسٹ کئی مہینوں سے خالی ھے - کوئی اچھا آفیسر جانے کے لئے تیار نہیں ھوتا ھے اس لئے آپ کو الاونسز بڑھانے کی ضرورت ھے -

میں براہ کارگل پر تھوڑا سا بولنا چاھتا ھوں - وھاں ایک ھی اسٹوڈیو ھے - ریڈیو کے لئے - اس میں آرٹسٹ کو لائین میں بیٹھنا پڑتا ھے کبھی میوزک کا ھوتا ھے کبھی ڈرامے کا اور کبھی کچھہ ھوتا ھے - اسٹوڈیو صرف ایک ھے - ھم نے کہا تھا کہ دوسرا اسٹوڈیو بنا دیجئے - ابھی تک اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا - اکوئپمینٹ آپکے پاس وھاں نہیں ھیں - ایک جھگڑا سا چپ ھے جو وھاں کے ملازم لوگ ھیں انکو کام کرنے کے لئے پوٹر نہیں

کتنے سال لگیں گے - جب کہ ھمارے بیس نکاتی پروگرام میں چھوٹے چھوٹے بجلی پروجیکٹ کو اھمیت دیا گیا ھے - اس اور بھی دھیان دینے کی ضرورت ھے -

اسی پرکار ایک اور چیز کی اور آپ کا دھیان دلانا چاھتا ھوں - لیہہ میں اسمال کوائنس نہیں ملتے ھیں- دوکاندار ماچس اور مٹھائی کے ذریعہ ٹرانزکشن کرتے ھیں - اسٹیٹ بینک والوں کا کہنا ھے کہ چیسٹ نہیں ھے - اس لئے میری خصوصی طور پر فائنینس منسٹر صاحب سے گزارش ھے کہ کم سے کم اس چھوٹے کے لئے چیسٹ کی ویوستھا کی جائے - ھمارے یہاں کی کل آبادی ایک لاکھہ تیس ھزار ھے - زیادہ چیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھہ تو وھاں پر اوشیہ بھیجیں جس سے وھاں کے نواسیوں کو اس طرح کی کٹھنائی نہ ھو -

وھاں جو مرکزی سرکاری ملازم طبقے ھیں انکے اب جو الاونسز ھیں یا ونٹر الاونسز ھیں اسٹیٹ گورنمینٹ کے مقابلے میں بہت ھی کم ھیں - میں نے فائنینس منسٹر صاحب سے ٹھیک اب کہا تھا - نتیجہ یہ ھے کہ جتنے بھی آفیسرس ھیں وہ وھاں جانا نہیں چاھتے ھیں کوئی

ہوتا ہے اور تو اور وہاں لیٹرین تک نہیں ہیں - پچھلی دفعہ میں نے اس سلسلے میں ایک کویسچن پوچھا تھا تو منتری جی نے جواب دیا تھا کہ بھئی جو شاملے اسٹاف کوارٹرس ہیں وہاں جانا چاہئے - باہر سے آرٹسٹ آئیں گے دوسروں کے ریزیڈینس میں اسکویٹنگ کے لئے جائیں گے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے -

وہاں پر کم سے کم لیٹرین کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک ریڈیو اسٹیشن ہے اسکے لئے ہونی چاہئے - یہ شرم کی بات ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری کے لئے - اسی طرح مانی ٹرنگ اکوپ منٹ نہیں ہیں نیوز کے لئے - نیوز کو مانی ٹرنگ کرنا پڑتا ہے آل انڈیا ریڈیو کو ٹیپ کرو ٹرانسلیٹ کرو اور پھر براڈکاسٹ کرو - نیوز ایڈیٹر کے لئے ٹیلیفون تک نہیں ہے - میں جو پوائنٹس آپکے نوٹس میں لا رہا ہوں انکو بہت سیریسلی دیکھ لینا چاہئے - ان چند الفاظ کے ساتھ جو آپ نے گرانٹس پیش کی ہیں اسکا سپورٹ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ پوائنٹس میں نے ریز کئے ہیں وہ کنسرن منسٹری کو بھیج دیں گے -

*SHRI M. KANDASWAMY (Tiruchengode): Hon. Mr. Chairman, Sir, I rise to make a few suggestions on the Supplementary Demands for Grants that have been brought before this House by the hon. Minister of Finance. The hon. Minister of Finance has sought the sanction of this House for spending a sum of Rs. 589 crores through these Supplementary Demands. Out of this, a sum of Rs. 75 crores is to be spent on drought relief measures in Tamil Nadu, Bihar, West Bengal and Rajasthan where almost all the districts are reeling under unprecedented drought. When one sees the serious drought situation prevalent in these States, he is constrained to feel that this sum of Rs. 75 crores is too meagre to touch the fringe of the problem; it is just like offering sugar-candy to the hungry elephant. I demand that more funds should be allocated for drought relief measures in these States.

Many senior Members, who preceded me, referred to the serious drought prevailing in their respective States. I would also like to refer to the frightening drought prevailing in Tamil Nadu. I will not be wrong in saying that drought has enveloped Tamil Nadu. In the Rajya Sabha, the hon. Minister of State for Agriculture has sent stated that the Government of Tamil Nadu has not sent any report about drought to the Central Government. At the same time, the hon. Minister of Revenue in Tamil Nadu Government, Shri S. D. Somasundaram, has stated that the Government of Tamil Nadu has already sent the report about drought to the Central Government. The AIADMK Member in this House has also referred to this in his speech the other day and nas confirmed about the drought report having been spent to the Central by the Government of Tamil Nadu. I do not know which is true and which is false. The people of Tamil Nadu are caught between the devil and the

*The original speech was delivered in Tamil.

(Shri Kandaswamy).

deep sea because of such misleading politics.

Irrespective of the fact whether a report about drought has been received from the Tamil Nadu Government or not, I demand that the Government of India should send immediately the officials team to assess the extent of drought and submit its report to the Centre. You know, Sir, that without such a report the Finance Ministry will not release money for drought relief. I appeal to the hon. Minister to despatch immediately the Centre's Team to Tamil Nadu and get the extent of drought assessed, after which the required financial assistance must be rendered for fighting the frightening drought.

Instead of fighting drought on a war footing, the Chife Minister of Tamil Nadu is implementing the nutritious food scheme, which costs annually Rs. 200 crores to the public exchequer. On the one hand the Government of Tamil Nadu is not lifting the foodgrains allotted under the National Rural Employment Programme and on the other hand the State Government is demanding huge quantities of food grains, more than the actual requirement. In order to create distrust in the minds of people about the Central Government, the State Government does not hesitate to charge the Central Government that required quantum of foodgrains are not being allotted to the State of Tamil Nadu. Unfortunately, 5 crores of Tamil people have become pawns in the political game of Chess. The skies have deceived the people. Their perennial river Cauvery is drying up. Their State Government has let them down without solving the basic problem of water. The Centre is too far away to come to their rescue.

The 1924 Cauvery Waters Agreement came to a close in 1974. The ruling party in Tamil Nadu, including the Chief Minister, Thiru MGR, is charging that the Cauvery waters dispute has assumed such gigantic proportions because of the indifference of Thiru Karunanidhi, the then Chief Minister of Tamil Nadu for about two years. After the close of this agreement in 1974, Thiru Karunanidhi was in office for just one year, during which period he was making ceaseless efforts in having a fresh agreement on Cauvery waters. He was frequently taking up with the Centre about the necessity for having a fresh agreement. Unfortunately, Thiru Karunanidhi's Government was not allowed to be in office for long after this.

What is the present Chief Minister, Thiru MGR, doing about this, after his party came to power? During the short intervening period of just one year, no agreement on Cauvery waters could be arrived at during the rule of D.M.K. between 1974 and the beginning of 1976. The AIADMK Government is in power there from 1977. The Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru MGR, is not attending even the meetings of Chief Ministers convened for discussing this issue. With all the force at my command, I charge that the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru MGR, has not shown any interest in getting Cauvery waters to Tamil Nadu.

I am afraid that the Karnataka Government is building up superstructures on the cemetry of 5 crores of Tamil people who are being roasted alive in drought because of failure of monsoon and because non-supply of Cauvery waters to Mettur Reservoir by Karnataka Government. The Mettur Reservoir has the capacity to hold 120 ft. of water. Today there is just 15 ft. of water in Mettur Reservoir. The districts of Thanjavur and Tiruchirappalli, which are known as the 'RICE BOWL' of Tamil Nadu and the adjoining districts of Periyar and Salem are fast becoming arid zones. One is alarmed at seeing the distressing news about drought in Tamil Nadu, which the national dailies are published day after day. Unfortunately, yet no action seems to have been initiated to fight this drought.

Sir, it is really regrettable that Karnataka is holding Tamil Nadu to ransom by not supplying Cauvery waters. The Government of Karnataka is emboldened to do this because it has constructed Haringi, Hemavathi and Kabini reservoirs at an investment of Rs. 250 crores on the tributaries of Cauvery without tahe approval of the Central Planning Commission, though the construction of such dams is prohibited on the rivers, which are covered by inter-state dispute. The people of Tamil Nadu are not far wrong when they feel that the Centre is in complicity with Karnataka State because no objection has been lodged with the State for construction of dams on Cauvery without the permission of Central Planning Commission. Sir, if Mettur Reservoir dries up, then Tamil Nadu inevitably dries up. Consequently the woes of 5 crores of Tamil people would be beyond any remedy. I demand that the Government of India must direct the Karnataka Government to supply adequate quantity of Cauvery waters to Mettur Reservoir immediately. Then only Tamil Nadu can be saved from extinction.

Tamil Nadu is also in the grip of inadequate electric power supply. On account of paucity of water, the generation of electricity in hydel projects has come to a standstill. Similarly, on account of non-availability of coal, the thermal electric projects are also on the verge of closure. In reply to a question on the floor of this House, it has been stated that the Kalpakkam Atomic Power Plant, near Madras, may take another decade to complete and to start power generation. It will be no exaggeration to say that Tamil Nadu is being enveloped by darkness from all sides—paucity of water and non-availability of electric power. I demand that more funds should be allocated for power generation in Tamil Nadu. More coal should be rushed to Tamil Nadu for generating more power in Thermal Station.

It is really unfortunate that after 1967 no big industrial unit under the Central public sector has been given to Tamil Nadu. When DMK was ruling Tamil Nadu we extended all the necessary help to the Centre in setting up Salem Steel Plant. Instead of utilising the ores available nearby and also the coal from Neiveli, now this Salem Steel Plant has just become a steel re-rolling mill. 1000 acres of land were acquired for this Steel Plant, and that land is still lying vacant. The people who gave this land have also not got job opportunities in Salem Steel Plant. While about Rs. 2000 crores have been allocated for Vizag Steel Plant in Andhra Pradesh, I wonder why this kind of step-motherly treatment be given to Salem Steel Plant in Tamil Nadu? Sir, I demand that Salem Steel Plant must become really a steel plant, according to its original project report. Steps should be taken in this direction by the Centre.

I need not tell that Madras is one of the four metropolitan cities in the country. Yet, there is acute drinking water scarcity in Madras city. No permanent solution to this problem has yet been found. The people are purchasing drinking water. After the removal of D.M.K. Government in 1976, while addressing a mammoth public meeting in Madras, our hon. Prime Minister assured the people of Madras that water from Krishna river in Andhra Pradesh would be brought to Madras city. Still this assurance has not seen the light of the day and the people of Madras city are facing severe epidemics in the absence of drinking water. I demand that the Centre should ensure that the problem of drinking water in Madras city is resolved immediately.

In these Supplementary Demands, more funds are being allocated for industrially backward areas. So far as Tamil Nadu is concerned, Salem district is industrially backward and more funds should be allocated for starting industries in Salem District. Unless there is industrial development in such of these backward areas, there is no

[Shri M. Kandaswamy]

redemption for the people of this area in the matter of getting job opportunities. The perennial unemployment problem can be solved only by starting more industries in industrially backward areas.

I find that sustantial sums are being spent on Radio and Television. Many hon. Members of this House have eagerly enquired about the Colour TV era in India. It is really a matter of regret and condemnation that in Madras TV more time is being allotted for Hindi features than for Tamil features. So far as Tamil people are concerned, they will not accept Hindi. They will close the TV if such open patronage is being extended to Hindi in Madras TV features. It is no use using, seeing them without knowing the language. I want that the Central Government should ponder over this question whether the imposition of Hindi on non-Hindi speaking people through Madras TV will not prove injurious to national integration. The people of Tamil Nadu are committed to national unity and they are an inalienable part of the nation. Yet the national integration is being jeopardised by this kind of encouraging Hindi in Madras TV. I demand that Hindi features in Madras TV should be restricted to 15 or 10 minutes a day as has been the practice so far. This is very essential to nurture and nourish national integration.

Before I conclude, I demand on behalf of D.M.K. that the Central Government should get the extent of drought in Tamil Nadu assessed by sending immediately a Team to Tamil Nadu and after that adequate funds must be allocated for fighting the drought in Tamil Nadu. The Government of Karnataka must be directed by the Centre to immediately supply substantial quantum of Cauvery water to Mettur Reservoir and thus save the people of Tamil Nadu. The Centre has settled the Farakka water dispute, with the neighbouring country, Bangla Desh. Similarly, the Centre must settle the Cauvery water dispute between the two States within the country.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): सभापति महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्ज फार ग्रान्ट्स तो पास होंगी ही। इस अवसर को मैं दो तीन बातें कहने के लिये इस्तेमाल करना चाहता हूँ।

पहली बात इंडियन आयल कार्पोरेशन के बारे में है। छः सात महीने पहले फैजाबाद में टांडा के स्थान पर एक डीजल पम्प शिड्यूल्ड कास्ट हरिजनों की श्रेणी के लिये विज्ञापित किया गया। उसके लिये हरिजन लोगों ने प्रार्थनापत्र दिये। लेकिन बाद में उसको जेनरल कैटेगरी में डाल कर वह डीजल पम्प किसी दूसरे को दे दिया गया, उन हरिजनों को नहीं दिया गया, उनका इंटरव्यू भी नही लिया गया। उसको जनरल कैटेगरी कर दिया गया। श्रीमान्, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां कुछ डीजल पम्पस बिक्री किये जा रहे हैं। मेरी बात आपको कुछ कड़वी लग सकती है। मैं यहां आपको स्पेसिफिक उदाहरण दे रहा हूं। बरेली में भूला का डीजल पम्प आपने विज्ञापित किया। उसके बाद नीचे से चार लोगों की लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में से जिसका नम्बर पहला और दूसरा था, उसको नहीं दिया गया बल्कि चौथे आदमी को वह पैट्रोल पम्प दे दिया गया। उनमें से एक आदमी ने आई० ओ० सी० के आफिसर के पास 20 हजार रुपया जमा करवाया था लेकिन आज तक उस मामले में दूसरे को डीजल पम्प दिये जाने के बाद भी उसका 10 हजार रुपया तो अफसर ने वापस कर दिया और बाकी 10

हजार अभी देना रहता है। न तो उसको डीजल पम्प दिया और न उसको उसका बाकी 10 हजार रुपया वापिस हुआ। इट इज इन माई पसर्नल नौलेज। यह आपके यहां डीजल पम्प देने के मामले में हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : आप पत्र लिखें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : पत्र लिखूंगा तो किसी को मालूम नहीं होगा इसीलिये मैं सदन में बता रहा हूं। मैं उस के संबंध में गवाही दिलवा सकता हूं। क्योंकि जिसने पैसा दिया, उसने पहले नहीं बताया, लेकिन जब उसको वापस नहीं मिला तो उसने बताया। दिल्ली से जाते समय उसने बताया कि उसको 10 हजार रुपया वापस मिल गया है। अब भी 10 हजार देने को बाकी रहता है।

तीसरी बात मैं यहां पर कुकिंग गैस की एजेंसी देने के बारे में कहना चाहता हूं। बरेली में आपने गैस की दो एजेंसी देने के सम्बन्ध में अखबारों में विज्ञापित किया। मैं आपको बस एक वही उदाहरण देना चाहता हूं, वहीं काफी होगा, स्थिति को समझने के लिए। करीब 7–8 महीने पहले आपने वहां वितरक को नियुक्ति करने के लिए जब विज्ञापन दिया, तो उसके लिए आपने कोई इंटरव्यू नहीं किया। सौ से ऊपर लोगों ने दरख्वास्तें दीं मगर किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। उसके बदले वहां के एक पूंजीपति, जो कि एक एम० एल० सी० भी हैं, उनके लड़के को एक एजेंसी और उस लड़के की जहां शादी हुई है, यानी उसके ससुर के निजि परिवार को दूसरी एजेंसी दे दी गई। अब वे दोनों वहां गैस की एजेन्सियां चला रहे हैं अराम से।

एक माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया हुआ . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार : उस लड़के की अभी शादी हुई है। उसमें से एक एजेंसी उसे मिल गई और दूसरी उसके ससुर के निजि परिवार की। इस तरह दोनों एजेन्सियां आपने एक ही परिवार में दे दीं और किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। यह आपके समय में हो रहा है। यदि आपने ऐसा ही करना है तो फिर सोश्यलिज्म आ गया। आप इसी तरीके से काम करते जाईये। जब भी कोई भूले भटके से मेरे पास आ जाता है और कहता है मुझे एजेंसी चाहिए तो मैं उनको यही कहता हूं कि मेरा इससे कोई सम्बंध ही नहीं है तेल मंत्री जानें। वे कहते हैं कि एक लाख रुपया दे दो तो एजेन्सी मिल जाएगी तो मैं कहता हूं कि आप दे दो एक लाख रुपया जा कर, मैं उसमें क्या कहूं। ऐसा आपके बारे में जनता का ख्याल है। आपकी पैट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक झलक मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से एक एम० एल० सी० के लड़के और उसके ससुराल वालों को गैस की एजेन्सियां दी गई। इन सब से यह विचार पुख्ता होता है कि आप कहां जा रहे हैं। आप इसकी जांच करवा लीजिए। मैं आपसे सही कह रहा हूं क्योंकि मेरे जिले का मामला है।

श्रीमन्, तीसरी बात में देहरादून के इण्डेन गैस के वितरक के बारे में कहना चाहता हूं। लगभग तीन चार साल पहले देहरादून की गैस वितरण करने वाली फर्म पर कानपुर के इंकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा और उस दौरान उस फर्म में जो गैस बुकिंग रजिस्टर होता है, वे उसको भी ले गए, जिसमें लोगों ने गैस लेने के लिए अपने नाम लिखाये हुए थे ताकि उनका नम्बर आने पर गैस मिल सके। जब इन्कम टैक्स के लोग उस रजिस्टर को भी उठा कर ले गए तो पिछले 3 सालों से वहां के

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

लोग काफी लिखत पढ़त कर रहे हैं, परेशान हैं, कि कम से कम उस रजिस्टर की फोटो कापी ही उन्हें मिल जाए जिससे वे पुराने रजिस्ट्रेशन को आधार मानकर गैस ले सके। क्योंकि उनके नाम उसी रजिस्टर में दर्ज हैं। यदि वे फिर से अपना नाम दर्ज करायेंगे तो उनको काफी समय बाद गैस मिलेगी, जबकि पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनका नम्बर जल्दी आ जाएगा। लेकिन वह रजिस्टर इन्कम टैक्स वाले वापस नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं चिट्ठियां नहीं लिखता हूं, मैंने इसके बारे में दो चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने बरेली के डिवीजनल आफिस के अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी हैं परन्तु मुझे उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। इस मामले के कारण देहरादून के हजारों लोग परेशान हैं। वे बेचारे आई० ओ० सी० के बरेली आफिस और दिल्ली आफिस को लिखते लिखते हार गए मगर अधिकारी इन्कम टैक्स वाले उस रजिस्टर को वापस कराने का नाम ही नहीं लेते हैं, जब कि उनका उस रजिस्टर से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। उसमें तो खाली लोगों के नाम ही दर्ज हैं। मैं उनको लिखता हूं तो मेरा भी जवाब नहीं मिलता. . . .'(व्यवधान).... इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई एकनालेजमैंट भी नहीं आया है ....

एक माननीय सदस्य : क्या उसका कोई एकनालेजमेंट भी नहीं आया ....

श्री हरीश कुमार गंगवार : जी नहीं, देहरादून वाले मामले में मेरे पास कोई एकनालेजमैंट भी नही आया है।

श्रीमन् यह हो रहा है। श्रीमन् मैं 15–20 मिनट से कम नहीं बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: You have already made three points.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: I have to cover many more points.

MR. CHAIRMAN: You have many points. There are many occasions when you can make those points. Now, in a phased manner, you can make those points.

SHRI HARISH KUMAR GNAGWAR: I am doing that.

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में बहुत से पिछड़े जिले हैं। उनके औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, यह सामने आनी चाहिये। मैंने पिछली दफा यह मामला 377 में में भी उठाया था। उसके ऊपर मेरे पास जवाब आया कि हमने एक कमेटी बिठा दी है जो यह पता लगायेगी कि कौन पिछड़ा जिला है, कौन पिछड़ा जिला नहीं है। अभी उद्योग मंत्री जी का वक्तव्य आया जिसमें यह बताया गया कि 82 जिले पिछडे रखे गये हैं। लेकिन उसका क्या अर्थ है। हमारे यहां नैनीताल-कम-बहेड़ी कांस्टीच्युन्सी है, उसमें ही सारे उद्योग धंधे जा रहे हैं। काशीपुर एक कस्बा टाइप का है और इसी में आता है। चाहे किसी किस्म का उद्योग धंधा हो सब वहीं जा रहा है। उसके सौन्दर्यकरण के लिए एक करोड़ रुपए की योजना है। अगर पेयजल की व्यवस्था हो रही है तो वहीं हो रही है, इलेक्ट्रोनिक्स का कारखाना जा रहा है तो उसी क्षेत्र में जा रहा है। दूसरे कारखाने जा रहे हैं तो वहीं जा रह हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप वहां की तरक्की न करिये लेकिन सभी जगह की बलेंसड तरक्की करिये।

मेरा पीलीभीत का पिछड़ा जिला है। वह वनों का इलाका है। हमने कहा कि

वहां पक पेपर मिल दे दीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं / वहां न कोई सरकारी उद्योग है और न ही कोई गैर-सरकारी उद्योग है ।

श्रीमन्, रामपुर, हलद्वानी में बड़ी लाइन पड़ सकती है लेकिन पीलीभीत का जिला जोकि नेपाल के बार्डर से जुड़ा हुआ है, वहां बरेली से पीलीभीत हो कर बड़ी लाइन निकालने की हम मांग करते हैं तो वह पूरी नहीं की जाती है । यह लाइन डिफेंस परपज के लिए बहुत आवश्यक है । इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती और इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां का कोई प्रभावशाली मिनिस्टर हमारी सरकार में नहीं है जो कि वहां उद्योग धंधे स्टार्ट करवाता, रेलवे लाइन डलवाता । सभी जगह रेलवे लाइन पड़ रही है । दक्षिण भारत में भी पड़ रही है । (व्यवधान) हम तो कहते कहते हार गये, लेकिन वहां बड़ी लाइन का कोई प्रपोजल सरकार ने नहीं बनाया । बरेली से पीलीभीत का सारा का सारा एरिया नेपाल वार्डर से लगा हुआ है और इस लाइन से डिफेंस की जरूरत भी पूरी होती है । इसके न होने से भी हमारे यहां उद्योग धंधे नाम की कोई चीज नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: You should confine youself to the Supplementary Demands. You can conclude now.

SHRI DHANIKLAL MANDAL: (Jhanjharpur): This is the only occasion when Members can ventilate their grievances.

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । पीलीभीत में शारदा नदी पर धनाराघाट में पुल बनना चाहिये । 62 की लड़ाई में चीनी लोग वहां तक कार ले कर आ गये थे । जब पुलिस को खबर की गयी तो पुलिस चार घंटे के बाद वहां पहुंची तब तक वे लोग चले गये । इस सारे काम में चार घंट लग गये । उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री का यह प्रपोजल था कि शारदा नदी पर धनाराघाट पर पुल बनाया जाएगा । बाद में लड़ाई खत्म हो गयी तो वह प्रपोजल भी खटाई में पड़ गया । डिफेंस के परपज से यह बहुत महत्वपूर्ण पुल है । इसकी स्ट्रेटिजिक इपार्टेंस है । इस पुल को स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने साधन नहीं हैं । यह कार्य सेन्ट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिये । शारदा नदी पर यह पुल बहुत जरूरी है क्योंकि पीलीभीत की सीमा नेपाल से मिलती है और नेपाल के जरिए से चीन से मिलती है । उस स्थान पर यह पुल बनना बहुत आवश्यक है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । 1969 में कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक विभाजन हुआ था । उसके बाद जो बम्बई का अधिवेशन हुआ था, चूंकि उस समय श्रमिकों में और जनता में बहुत बड़ा असन्तोष था, उसको समाप्त करने के लि और उनको अपने पक्ष में करने के लिए माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने जो कि इस समय सदन में उपस्थित हैं, उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा । लेकिन वह 1969 से ले कर आज तक नहीं हुआ । कांग्रेस सरकार हर दफा इसको दोहराती रही है कि नेशनलाइज करेंगे लेकिन वह 1982 तक नहीं किया गया । अब सुना है कि किसी कारणवश सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है । प्राइवेट गन्ना फैक्टरियां क्या कर रही हैं ? नेशनलाइजेशन के डर से हर साल लोन ले लेती है और जिस काम के लिए वे लोन लेती हैं, उस काम पर वह खर्च न कर,

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

उसमें से अपनी कमाई निकाल लेती हैं और अपनी पाकिट में डाल लेती हैं। श्रमिकों की ग्रेच्युटी नहीं देती, उनका प्राविडेंट फंड नहीं देतीं। वे किसानों का पैसा नहीं दे रही हैं वे यह सोचती हैं कि अगर नेशनेलाइजेशन हो जाता है तो उनको इस पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ेगा तमाम पैसा सरकार के जिम्मे पड़ जाएगा। यह हालत आज चीनी मिलों की है।

हमारे पीलीभीत में एक प्राइवेट चीनी फैक्टरी है। वहां 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की फर्जी पर्चियां बनायी जाती हैं। फर्जी पर्चियां इस तरह से बनायी जाती हैं। तौल केन्द्र पर 25 क्विंटल गन्ना किसान का तौला गया लेकिन किसान की पर्ची पर 20 क्विंटल गन्ना लिखा गया उसका पांच क्विंटल गन्ना मार लिया। उस पांच क्विंटल की एक्स्ट्रा चीनी बना कर बिना एक्साइज ड्यूटी दिए चीनी बाहर निकाल कर बेच दी। शाम को उस गन्ने की फर्जी पर्ची बना दी। यह सब एक्साइज इंस्पेक्टर से मिलीभगत से होता है। पीलीभीत की इस शूगर फैक्टरी के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं होती है क्योंकि उसके मालिक एक मंत्री के बहुत बड़े भक्त हैं। कोई भी शिकायत करता रहे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती। श्रमिकों का लाखों रुपये का प्राविडेंट फंड जमा नहीं किया, ग्रेच्युटी का पैसा जमा नहीं किया है।

इसी तरह से रेल के डिब्बों में दो सौ क्विंटल माल की कपेसिटी है लेकिन तीन सौ क्विंटल माल लाद दिया जाता है और किराया दो सौ क्विंटल का देते हैं। स्टेशन मास्टर की मिलीभगत से यह सब होता है। इसकी जांच हुई और यह बात सही पायी गयी उसके बावजूद वह स्टेशन मास्टर वहीं है। सरकार के कान पर ऐसी बातों की जूं नहीं रेंगती। बारबार मैं खतों के जरिए कह रहा हूं कि सरकार को चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं।

ऐसे ही एक मझोला शूगर फैक्टरी पीलीभीत है। उसके शीरा क्लर्क रशीद अहमद पारो हैं। जब उसने यह देखा कि तीन लाख रुपए का शीरा जनरल मैनेजर बेच कर हजम कर गये हैं तो उसने चिट्ठी लिख दी कि इसकी जांच की जाये। जनरल मैनेजर ने उसकी जांच से पहले ही उसको सस्पेंड कर दिया। आठ महीने हो गये वह अभी तक सस्पेंड है। इस बीच में जांच हुई और शिकायत सही पायी गयी शीरा क्लर्क रशीद अहमद पारो के विरुद्ध कोई आरोप नहीं पाया गया लेकिन जनरल मैनेजर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ और वह शीरा क्लर्क अब तक सस्पेंड है। यह ऐसा ही है जैसा कि मारुति के मामले में माननीय उन्नीकृष्णन् ने यहां मामला उठाया था कि गवर्नमेंट ने सी० एफ० ब्राउन का कांट्रेक्ट क्यों कैंसिल कर दिया और दूसरी इटैलियन फर्म को दे दिया? बजाए इस बात की जांच होती यह जांच की गयी कि यह भेद और कागज कैसे लीक हुये। इस के लिए अफसरों को सस्पेंड किया गया और कुछ को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया। ऐसा ही इस फैक्टरी में भी हुआ। जिस पर कोई चार्ज नहीं उसको तो सस्पेंड कर दिया गया और जिस अफसर के खिलाफ जांच हुई और शिकायत को सही पाया गया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि शूगर मिलों की पालिटिक्स सारे देश में है। वह चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यू० पी० हो, सब जगह की शूगर फैक्टरी वाले चुनावी राजनीति चलाते हैं। इसीलिए सरकार इन के मिल-मालिकों का कुछ नहीं बिगाड़

पाती और इनकी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती ।

पहली मेरी मांग यह है कि कृषि की उन्नति के लिए कृषि बीमा योजना शीघ्र लागू की जाये ।

अगर आप चौखंभा राज्य चलाना चाहते हैं तो जिस तरह से पार्लियामेंट, असेम्बली में और नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में बजट होता है, उसी तरह से ब्लाक और ग्राम पंचायत का बजट भी उनके हाथ में दीजिए, उसको पास करने दीजिए । उनके पास कोई साधन नहीं हैं। कैसे उन्नति होगी । तालाब चले गये, जमीनें चली गयीं, कुछ नहीं रह गया, प्रधान क्या करेगा ?

इसी प्रकार गांवों को सड़कों से जोड़िये । यदि आप सही माने में देहात का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो शिक्षा, बिजली से पहले सड़क दीजिए। इसके बिना ग्रामीण क्षेत्र का भला नहीं हो सकता।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है । यह इसलिए हो रहा है कि जिला परिषदों के हाथ से स्कूलों को ले लिया गया है और ये सरकार के हाथ में चले गये हैं । इस ओर भी ध्यान दीजिए और इनकी हालत में सुधार करवाइए । कान्वेंट स्कूल में सभी साधन उपलब्ध होते हैं और प्राइमरी स्कूलों में जहां पट्टी पर बैठना पड़ता है, कई बार तो पट्टी भी घर से लानी पड़ती है, इन विद्यार्थियों में कैसे समानता लायी जाएगी । एक बच्चा कलेक्टर और कमिश्नर बनेगा और दूसरा जो पट्टी पर बैठता हैं वह क्या बनेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि कान्वेंट स्कूलों को समाप्त करके शिक्षा में एकरूपता लायी जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Sir, I may make it clear to the House that two hours have been allotted to this Bill. There are two more Bills pending. My friend, Mr. Gangwar, has already taken more than half-an-hour.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR: No, Sir. I have started at 3.16 hrs. I have taken only 16 minutes.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: At this rate I do not think we can finish it even in two days. Sir, you must adjust the time allotted for this Bill with the number of speakers so that each Member may be given minimum time.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Dhanik Lal Mandal will be very brief.

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय कभापति महोदय, मैं इन मांगों पर चर्चा करते हुए आपके माध्य म से सरकार का और इस सदन का ध्यानएक गंभीर समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं ।

महोदय, विगत 13 अक्तूबर को मैं और मेरे दूसरे दलों के साथी अकाली सत्याग्रहियों की जेलों की दशा देखने के के लिए पंजाब गये थे । सबपसे पहले हम लोग बहादुर गढ़ किले में गहुंचे । वहां लगभग 2500 सत्याग्रही रखे गए थे यह एक पुराना किला है, लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष पुराना । वहां पर जो हम लोगों ने देखा, वह सचमुच में हृदयविदारक था । अब चूंकि सत्याग्रही छोड़ दिए गए हैं इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अब वह अप्रसंगिक होगा, लेकिन उससे सम्बन्धित दूसरे बिन्दू की चर्चा करना चाहूंगा कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो सत्याग्रहियों को देखने के बाद सत्याग्रहियों ने कहा कि यहां बिहार के भी

[श्री धनिक लाल मंडल]

बंदी हैं, जिनको चलकर आप देखिये । मुझे ताज्जुब हुआ कि बिहार के बन्दी कैसे पहुंच गये हैं । मेरी जब जिज्ञासा बढ़ी तो मैं उनको देखने के लिए गया।

लगभग तीस लोगों से मैं मिला जो बिहार के विभिन्न हिस्सों से पंजाब में काम करने के लिये गए हुए थे और जिनको पकड़कर जेल में रख दिया गया सत्याग्रहियों की सेवा शुश्रूषा करने के लिये।

यह कहा जा सकता है कि हम एक-पक्षीय बात कर रहे हैं। जब उनका चालान हुआ होगा, उनको जेल में रखा गया होगा, हम जो कह रहे हैं वह एक पक्षीय बात है। लेकिन मैं इस तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा – माननीय पण्डित जी यहां हैं – कि बहादुरगढ़ कोई जेल नहीं है। बहादुरगढ़ को फौरी तौर पर सत्याग्रहियों को रखने के लिये एक नोटिफिकेशन करके जेल का रूप दिया गया । वैसे वह कोई जेल नहीं है। वह साढ़े तीन सौ वर्ष पुराना किला है । वहां जंगलात हैं, उसमें सांप, बिछू आदि सभी प्रकार के जीव-जन्तु पाए जाते हैं। फिर, बिहार के तीस आदमी वहां कैसे पहुंच गए। यदि उन लोगों ने कोई अपराध किया और अपराध करने के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया और बजाय पंजाब के किसी जेल में भेजने के उनको बहादुरगढ़ किले में क्यों भेजा गया। इससे मेरा संदेह बहुत ही बढ़ गया । इसलिये, मैं सरकार से बार-बार निवेदन कर रहा हूं, दूसरे मौके का भी मैंने प्रयोग किया कि इन तीस बिहार के लोगों को मैंने बहादुरगढ़ फोर्ट में पाया।

सरकार यह कहती है कि वे लोग सचमुच अपराधी हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे थे इसलिए गिरफ्तार किया गया और इसीलिये जेल भेजा गया। लेकिन बहादुरगढ़ तो जेल नहीं है, वह तो पुराना किला है । सत्याग्रहियों को जगह नहीं रहने की वजह से या किसी और कारण से पंजाब की सरकार ने उचित समझा कि उनको बहादुरगढ़ किले में रखा जाए। बहादुरगढ़ किले में बिना टिकट यात्रा करते हुए यात्रियों को भेजने का क्या रहस्य हो सकता है? मैं बहुत ही अदब से सरकार से यह मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये, दोषी अफसरों को सजा मिलनी चाहिये और उन लोगों को जेल से रिहा कर देना चाहिए।

मैंने बात शुरू की है बिहार से, लेकिन पंजाब से संबंधित हो गया, इसलिये पंजाब के संबंध में इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि हिंसा चाहे किसी की तरफ से हो या अकालियों की तरफ से हो, हम उसकी भी निन्दा करते हैं। हम उसको कोई शाबाशी नहीं देते।

प्रो० ए०न० जी० रंगा: कई दफा।

श्री धनिक लाल मंडल: मैं एक ही बात कह रहा हूं, चाहे हिंसा किसी भी तरफ से हो या सत्याग्रहियों की तरफ से हो। सत्याग्रिहियों को हिंसा करनी ही नहीं चाहिये। कंकड़, पत्थर, ढेला, नहीं फेंकना चाहिये। इसलिये, मैंने कहा कि हिंसा चाहे किसी की तरफ से हो उसकी निन्दा होनी चाहिए।

पंजाब में अभी जो कुछ हो रहा है और जिस ढंग से उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, मेरी इसमें आशंका है कि हम लोग स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, सरकार स्थिति को बिगाड़ रही है, सरकार स्थिति को ठीक से संभाल नहीं रही है। पंजाब की यह जो सिख कम्युनिटी है, बहुत ही सेंसिटिव और वोलेटाइल कम्युनिटी है। इनकी समस्याओं को जिस तरह से

हमको सुलझाना चाहिये, इनके आन्दोलनों को किस तरह से सुलझाना चाहिये, वह रास्ता हम अख्तियार नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको यह आशंका है कि मामला और गम्भीर बन सकता है । इसलिये मैं हिंसा की निन्दा करते हुए सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार अकालियों की उचित मांगों की जल्दी से जल्दी पूर्ति करे । उनकी जो वाजिब मांगें हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिये ।

SHRI P. NAMGYAL: Do you want greater autonomy?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Why not? why not greater autonomy for Punjab? What is wrong in it? I have conceded it so many times.

उनकी वही एक मांग नहीं हैं । एक मांग को कहीं से आप उठा लेंगे और हवा बनाएंगे, जैसे अभी आपने कह दिया कि ट्रेटर्ज और आसानी से कह दिया तो यह ठीक नहीं होगा और एम० पी० को तो कम से कम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, अपने ऊपर काबू रखना चाहिये ।

मैं कह रहा था कि अकालियों की मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । मेरी श्री प्रकाश सिंह बादल से बात हुई है । मैं उनसे मिल आया हूं । सरकार जो नैगोशिएशंज की बात करती है उससे वे लोग इन्कार नहीं कर रहे हैं । उनका कहना है कि अकालियों की जो मांगें हैं उन पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिये, वह सुस्पष्ट होना चाहिये । किन मांगों को सरकार वाजिब समझती है और किन को नहीं, यह पता लगना चाहिये । मैं जेल में बादल जी से मिला हूं । तेरह तारीख को मैं गया था, बहादुरगढ़ से नाभा और लुधियाना । लुधियाना की जेल में मैं श्री बादल जी से मिला था । मैंने भी यही भाव व्यक्त किये थे । मैंने कहा था कि पहली बात तो यह है कि हिंसा नहीं होनी चाहिये । दूसरी, देश की अखंडता को ध्यान में रख कर ही कोई बात हो सकती है । इन दोनों बातों से वह पूर्णतः सहमत थे । उन्होंने स्वीकार किया कि सत्याग्रही को हिंसा नहीं करनी चाहिये । दूसरे, जहां तक देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात है, उससे भी वह सहमत हैं । उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिये । उन्होंने कहा कि हम लोग हिन्दुस्तान में रहते हुए, हिन्दुस्तान के संविधान को स्वीकार करते हुए, हिन्दुस्तान की अखण्डता और प्रभु-सत्ता को स्वीकार करते हुए जो हमारी बिल्कुल वाजिब मांगें हैं, उनको तो सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये । मैंने उनसे पूछा कि सरकार यदि वार्ता के लिये तैयार है तो क्या आप वार्ता करेंगे ? उन्होंने कहा करेंगे । लेकिन इसके पूर्व प्रधान मंत्री जी से तथा और लोगों से वार्ता हो चुकी है लेकिन मामला एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है । जब मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो रावी, व्यास नदी के पानी के बटवारे के बारे में हमारी मांग यह है कि एक कमिशन नियुक्त होना चाहिये और वह जो भी फैसला करेगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे । कैसे हम उनको ट्रेटर कह सकते हैं? माननीय सदस्य ने तो बहुत आसानी से ट्रेटर कह दिया है । माननीय सदस्य काश्मीर सरकार से जब बात करने का मामला आता है, उस वक्त तो सिसेशनिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब सिख बात करना चाहते हैं .....

श्री पी० नामग्याल : हम स्टेट आटोनोमी के बाहर जाकर बात नहीं करते हैं । जो मांगें हैं, वे स्टेट के अन्दर रहते हुए ही हैं । आप को गलत-फहमी है ।

श्री धनिक लाल मंडल : जिस तरह से आप मांगें कर रहे हैं, वैसे ही वे भी कर रहे हैं । सिसेशनिस्ट होने की बात क्यों करते हैं ।

चण्डीगढ़ के मामले को आप लें । चण्डीगढ़ पंजाब का है, यह साफ बात है । इसको स्वीकार किया जा चुका है । जब पंजाब और हरियाणा बने थे, तब यह तय हो गया था कि चंडीगढ़ पंजाब का है । बादल जी ने कहा कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिल जाना चाहिये । उसमें भी उन्होंने कहा कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का पंच बना दिया जाये और उसका जो भी निर्णय होगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे । ऐसी रीजनेबल बात जो आदमी कर रहा हो, उसके बारे में इस तरह की हवा बनाना मैं समझता हूं कि स्वस्थ वातावरण बनाने का काम नहीं है ।

अब मैं बिहार के संबंध में एक दो बातें कहना चाहता हूं । शास्त्री जी ने जो आंकड़े दिए, सही दिए । मैं दोहराऊंगा नहीं । मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है । जब कि सरकार को निर्णय करना चाहिये । सत्यता के परीक्षण की यह घड़ी है ।

बिहार में सम्पूर्ण रूप से अकाल है । इस बात से इन्कार करना सत्य को झुठलाना है । इसलिये मैंने कहा यह सदन सत्य का घर है, सब के लिये और इस सत्य तथ्य को स्वीकार कर वहां के लोगों की जो मांग है कि बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करना चाहिये, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये । उधर के माननीय सदस्य कह सकते हैं कि इससे केन्द्र सरकार का क्या संबंध बनता है ? मैं कहना चाहता हूं कि यह संबंध बनता है कि जिस पार्टी की सरकार यहां है, उसी पार्टी की सरकार बिहार में भी है और हम बिहार से आते हैं, वहां की जनता को हम नहीं बांट सकते हैं, राज्य और केन्द्र में । तो हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी तरफ से मेरा कहना है कि बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करके तत्काल राहत का काम किया जाना चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो स्थिति हाथ से बाहर निकल जायेगी । जब काबू से बाहर हो जायेगी तो फिर हम लोग पीछे चल कर के सम्हालना भी चाहेंगे तो नहीं सम्हाल सकेंगे ।

बाढ़ के बारे में मेरा निवेदन है, पांडे जी यहां बैठे हुए हैं, बहुत जोर से यहां कहते हैं कि जो हिमालयन् रिवर्स है, उनके संबंध में हमारी नेपाल सरकार से बातचीत हो रही है । जिस जिम्मेदारी से माननीय पाण्डे जी कहते हैं उसी जिम्मेदारी से हम भी कहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी समझौता करके कोई रास्ता निकालें । यह क्यों कह रहा हूं ? इसलिये कि बिहार की सभी नदियां नेपाल होकर आती हैं और उनकी वजह से बाढ़ और सूखा होता है । वहां जो नदियां हिमालय से निकल कर नेपाल होकर बिहार में आती हैं, उनको यदि नियंत्रित नहीं किया जायेगा तो बिहार को अकाल और बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता है । क्योंकि पहले तो पानी बाढ़ लाता है और जब पानी ड्रेन आउट

करके गंगा द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है तो सुखाड़ पड़ता है । इसलिये हमारी मांग है कि पांडे जी आप हमें केवल आश्वासन न दें, बिहार तो यों ही लगता है कि वह नासूर बन रहा है, पूरे देश का, लेकिन यह हमारे लिये कलंक की बात है । हमको उसको बचाना है । इसलिये गंगा या कोसी बेसिन पर समझौता कर के उसको नियंत्रित कर के बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से बचावें । यही मेरी प्रार्थना है ।

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Mr. chairman, I am happy that 11 hon. Members have taken part in this discussion and have made, quite valuable suggestions. They have also touched the problems in their respective areas according to what they feel. But I am surprised to note that the hon. members, some of them, who have spoken on the subject, are absent in the House even to hear my reply. I do not know whether it is worthwhile replying to their questions: yet I try to tell what I feel about them one by one.

The first speaker, Mr. Sudhir Giri, asked for grant for natural calamities. It is a reasonable request. But he must bear in mind about the availability of the fund at the Centre.

16.50 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*

It is not as if it is from a well that we are drawing water. It is according to the money that we have, that we have to give it to the States.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: You are wasting money on ASIAD!

SHRI PATTABHI RAMA RAO: That is absolutely in the interests of the country. Our name will go up in the world. We have to encourage youngsters and sportsmen. You and I are old people. We may not understand it. The youngsters will know it .... (*Interruptions*)

SHRI DHANIK LAL MANDAL: People are dying in ASIAD.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: ....even if people die. (*Interruptions*). That is not the question. You should never compare ASIAD games and people dying. By overage some people die. We cannot help it. They have lived enough and they die. We cannot help it. That question does not arise. Being a senior member you should not compare them; do not bring in those deaths in connection with ASIAD. ASIAD is an absolute necessity. It brings us credit and youngsters will be encouraged.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There should be some veterans' race in which you and Mr. Mandal can participate. That is why he is referring to ASIAD.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: I cannot do it, but he may do it. He will win it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If there is a world Ministers veterans' race, then Mr. Mandal and you also can participate in it.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Thank you.

The Budget provision of Rs. 103 crores for non-Plan grants to States on account of natural calamities has become inadequate in the wake of unprecedented floods in Bihar, Orissa, Uttar Pradesh and Assam, besides devastating cyclone in Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu in the current financial year. An additional Supplementary Grant of Rs. 75 crores has therefore been required.

Shri Girdhari Lal Vyas raised the problem faced by Rajasthan on account of severe drought. The Rajasthan Drought Central Team visited the State from 4th to 7th May, 1982. The ceiling of expenditure approved on the basis of the recommendation of the Team is Rs. 37.03 crores. Against this, an on account payment of Rs. 20 crores has since been released.

[Shri Pattabhi Rama Rao]

Shri J. S. Patil said that the agricultural prices are not remunerative. As the House is aware, agricultural prices are revised each year, having regard to the cost of the inputs and other factors and also keeping in mind the consumers on one side. If the prices are increased abnormally, the price the consumer has to pay will also go up. So, balancing these two, the prices have been given and apart from that the Agricultural Prices Commission recommends every year after taking all these into consideration. I am sure that this year the Government have been more liberal than the recommendations made by the Commission.

Mr. Patil also referred to the deficiencies in the implementation of the mid-day meals programme for Scheduled Castes/Scheduled Tribe and other poor children in Maharashtra's primary schools. This programme is entirely a State subject and we can give some assistance when it is possible. Actually, it is the State that has to look to such programmes as these and the Government of India does not come into the picture.

Shri Arjun Sethi referred to the Supplementary Demands of Rs. 200 crores for fertilizer subsidy. This demand has been necessitated not only on account of higher cost of production at Ramagundam and Talcher Projects but also due to increase in the cost of inputs and utilities of various fertilizer units in the country. There had been a steep increase in the input costs—naural gas, fuel, oil, naphtha, etc. Therefore, the retention prices had also to be increased. No doubt, he has supported the Supplementary Demands, but he has referred to the drought conditions in Orissa.

The Orissa Government sent a request for assistance of Rs. 57.93 crores. A central team has visited the State to assess the quantum of assistance and a decision in this regard will be taken after further discussion with the State Government, which is considered necessary.

There are further reports of drought continuing in the State. But a detailed memorandum from the State Government in this regard is awaited.

For cyclone relief, the State Government sought assistance of Rs. 125.44 crores. Against this, ceiling of expenditure sanctioned by the Central Government is Rs. 56.56 crores and Rs. 25 crores have been released so far.

For flood relief, the amount asked for by Orissa is Rs. 618.40 crores. The central team had visited the State and its report was considered by the high level Committee on 15.10.82 and a decision on the quantum of assistance to be released to the State Government will be taken shortly. Meanwhile, 'on account' payment of Rs. 30 crores has been made.

My good friend, Shri Chitta Basu, referred to the recovery of loan provided by the Government of India to clear the amount of overdraft incurred by the West Bengal Government during the first three months of 1982 i.e. January to March, within the current year. The hon. Member has an erroneous impression of the arrangements made for the clearance of States' overdrafts at the end of March, 1982. The recovery of loans provided to cover overdrafts incurred during the first three months of the current financial year viz. April to June will be effected within this year. This is logical as the excess deficit was resorted to in the current year.

It may also be mentioned that the Central Government has already given loans of Rs. 1743 crores for clearing the deficits of States up to 31.3.82.

PROF. N. G. RANGA: Is it for the whole country?

SHRI PATTABHI RAMA RAO: For the whole country.

After all, the resources of the Central Government are also limited and it cannot assume unlimited burden on account of State Governments.

17 hrs.

Shri Chitta Basu referred to the allocation of the market borrowings between the Centre and the States during the Sixth Plan. The allocation of market borrowings is only one element for financing the Plan outlays of the States, for which a significant contribution comes by way of Central assistance. To the extent the market borrowings for States were increased, the capacity of the Centre to contribute to the State Plans would have been affected. So, it would have made no overall effect.

Shri Chitta Basu also referred to the fact that the supplementary demands do not include anything for drought, which shows that the Centre is insensitive to drought. The budget estimates for 1982-83 include already a provision of Rs. 100 crores for drought. This, together with some savings expected from some other provision, is considered adequate for the time being. Drought conditions are being reported from various parts of the country only now and, unless an assessment is available of the requirement of funds, based on the reports of Central study teams that are going to visit various States, it would be premature to go in for additional funds.

Shri Ramavatar Shastri also spoke about the drought conditions and the difficult position of the States. As I stated already, the study teams are going to various States from where reports of drought have come, to see what exactly is the position and, as soon as their reports are received, they will be considered and we will see what exactly can be done.

Shri Namgyal, who comes from the highest peak in India, has referred to some of the problems of his region, which have got to be redressed as early as possible. We shall certainly go into each one of them, including the telephone exchange about which he spoke, and see what best can be done.

Shri Kandaswamy spoke in Tamil, but I was able to follow the English translation. I can assure him that more money is not given to the Vizag Steel Plant then to the Salem Steel Plant. Actually, the Salem Steel Plant has gone into production, whereas even the construction of the building has not started, so far as the Vizag Steel Plant is concerned. That is the difference. I am sure my predecessor, Shri Subramaniam has helped that State very much earlier in seeing to it that the Salem Steel Plant came into being. I would not say that came in our way, but anyway he helped the Salem plant, which has gone into production already. Certainly, Government will encourage it, as it is in the public sector.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you have an opportunity to help the Vizag Steel Plant.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: The Finance Minister considers all States as equal. Shri Pranab Mukherjee has got a very good balanced mind. He will take interest in every State equally.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI. What about drought? Will you declare Bihar a famine area or not?

SHRI PATTABHI RAMA RAO: The team is going to those areas. The team will assess the position.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: After the Report of the Team you will declare.

(Interruptions)

SHRI PATTABHI RAMA RAO: Mr. Gangwar has spoken on the subjects which do not come under the Grants, about petroleum etc. I would request him or suggest to him that he may write to the concerned Ministries

[Shri Pattabhi Rama Rao]

or Ministers to see that these points are sorted out.

Then, finally, Mr. Mandal, a seasoned politician and a former Minister, has spoken about the conditions of jails in Punjab and also about Bihar. We will look into all of them and see what best could be done.

Sir, I do not want to take more time of the House since we have to pass the Supplementary Demands.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What about the Bombay strike? You did not say anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You don't divert his attention.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: We are good friends. We can talk outside.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You meet him separately.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: So, Sir, I move that the Supplementary Demands for Grants be passed.

MR DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ramavatar Shastri and Mr. Shamanna moved cut motions. I hope they have no objection for putting their cut motions together.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions to the vote of the House.

Cut motion Nos. 4 to 15 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1983, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demand Nos. 2, 12, 13, 14, 18, 26, 30, 31, 41, 42, 43, 55, 59, 62; 63, 64, 69, 71, 78, 79, 80, 82, 91; 92 and 98."

The motion was adopted.

17.06 hrs.

APPROPRIATION (NO. 4) BILL**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payments and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1982-83."

The motion was adopted.

SHRI PATTABHI RAMA RAO: **

Sir, I introduce the Bill.

Sir, I beg to move:

Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dt. 19.10.1982.

**Introduced with the Recommendation of President.